

Title: Presentation of the 6<sup>th</sup> Report of the Business Advisory Committee.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to present the 6<sup>th</sup> Report of the Business Advisory Committee.

The BAC, at its sitting held on Tuesday, the 25<sup>th</sup> November, recommended allocation of time to the following items of business as shown against each.

1. Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 – one hour
2. The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014 – two hours. ....(Interruptions)

I have to read it out. I understand it. It is over, but this was decided. ....(Interruptions) They were passed. I understand it. ....(Interruptions) Tomorrow, you will say otherwise. This was the decision of the BAC for allocation of time. This has to be brought to the knowledge of the House. I understand what you are saying. Today, the next BAC meeting was held. You will not decide it.

Sir, what is his problem? Is he trying to educate the Ministers? ....(Interruptions) The procedure has to be followed. They cannot come this side and so they should relax for a while. This was the time allocated and this is what has come from the Business Advisory Committee. ....(Interruptions) This is completed but this was the time allotted. You can have objection to it... (Interruptions) These were the five business items for which time was allotted and all have been concluded. Time was allotted for the IATA Bill, The Central Universities Bill... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : The hon. Minister is informing the House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The following business after this will be brought and this is the directive of the hon. Speaker to read it out, why do you have objection to that?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you please read it out.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I have read it out. If the direction had not come from the hon. Speaker, I would not have done it. So, this is a procedure which has to be followed. If you are not ready to follow the procedure, then I cannot help it. (Interruptions) It does not indicate any big sign of intelligence. I have already read it out. It takes two minutes but then you have created so much noise as if we do not understand... (Interruptions) I have read it out. It is over. What is the anxiety about it? I have read it out already. Professor does not have patience of one minute... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Members thought that you will be speaking on black money.

\*m05

**श्री तारिक अनवर (कट्टार):** सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा, इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो जाए। अभी यहाँ लोक सभा में और शज्य सभा में कल बैंक मनी, काले धन पर बहस चल रही है और कल शज्य सभा में इस पर बहस समाप्त हुई और वहाँ वित मंत्री ने उस बहस का उत्तर दिया। लेकिन उनका उत्तर बहुत ही निराशाजनक रहा, ऐसा लगा कि छापे वित मंत्री बहुत मजबूर हैं, असहाय हैं और उनके द्वारा बंधे हुए हैं। उनका जो उत्तर अखबारों में आया है, उसे मैंने पढ़ा है, उसे ऐसा ही लगा कि वह कुछ भी करने में असक्षम हैं। यहाँ कल से बहस चल रही है, छापे बहुत से माननीय सदस्यों ने सरकार को यह सलाह दी है कि सौ दिनों के अंदर तो नहीं, बल्कि छः महीने के अंदर भी कालेधन की वापसी की कोई उम्मीद ठिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए बेहतर यह होगा कि सरकार देश से और देश की जनता से माफी मांग ले कि उन्होंने लोक सभा बुनाव में जो प्रवार दिया, जो देश की जनता को श्रमित और गुमराह किया, उस दिशा में अब कोई लोक कदम नहीं उठ रहे हैं। इसलिए यह बेहतर यह होगा कि यह देश की जनता से माफी मांग लें। मैं भी यही सलाह द्वारा, वर्षोंकि कालेधन का जो मामला है, यह इस सरकार के लिए गते की छड़ी बजने वाला है। गते की छड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वर्षोंकि इन्होंने देश की जनता को कुछ ऐसे सपने दिखाये और तीन उस सपने और योसे में आ गये, लोगों ने इनकी बात पर परिष्कार कर दिया। जैसा अभी कहा गया कि देश के दूर नागरिक के खाते में लाखों रुपये जमा होंगे, 15 लाख रुपये तक की राशि जमा होंगी। देश की जनता ने, देश के गरीब लोगों ने, किसानों ने उस 15 लाख को सामने रखकर कि अब तो मोटी जी प्रधान मंत्री बन गये हैं, अब 15 लाख रुपये छापे खाते में आने ही वाले हैं। उन्होंने आगे की योजनाएं बना रीं, अपने बच्चों के अधिकार का फैसला कर दिया। उनको अच्छी शिक्षा देने की बात सोच रही है और इस तरह से एक लोगों को एक नवाचारणी पैदा हुई। अब छः महीने बीत चुके हैं और अब छापे वित मंत्री जी यह कह रहे हैं कि बहुत सारी पैदीदरियां हैं, बहुत सारी संधियां हैं, जिसके कारण छम लोगों के नाम नहीं बता सकते हैं। इस दिशा में छम कदम नहीं उठा सकते हैं। अब देश की जनता को एक भूत-भूतैया में डालने की कोशिश हो रही है। प्रधान मंत्री के पृथ्वी के रूप में नैरेंद्र मोटी जी ने वसा कहा? अभी नायदू साफव ने कहा कि छमने अपने मैनिफेस्टो में सौ दिन का कोई जिक्र नहीं किया है। लोकता है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह बात नहीं रखी है, लेकिन महोदय, ये दुरिया जानती है, सारी मीडिया में ये खबरें रही थीं, यह दिखाया गया था, प्रधान मंत्री जी ने बहुत ज़ोर दे कर यह बात कही थी कि अगर उनको प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला, अगर उनकी सरकार आई तो सौ दिनों के अंदर छम काले धन को ता कर दिखाएंगे। लोगों ने उनकी बातों पर परिष्कार किया और उनको बहुमत दिया। लेकिन आज वही नैरेंद्र मोटी जी कह रहे हैं कि छमने नहीं मालूम कि कितनी राशि बाहर है। उसका कोई तेज़ा-जोखा नहीं है। मोटी जी ने खर्च की बात आज तक का बिल 85 लाख करोड़ रुपये का काला धन रिटेन्शन में जमा है। भाजपा के बाबा शमदेव ने तो यहाँ तक कहा कि 385 लाख करोड़ रुपया काले धन के रूप में रिटेन्शन में है। उसका देश में वापस लाने का वर्तन भी उन लोगों ने दिया था। लेकिन याता में आगे के बाबा मोटी जी का रुखा बदल गया। अब काले धन की मात्रा के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही जा रही है। विषय से सता में आगे के बाबा शमा बदल गई। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद विशिकांत द्वारा जी की बात याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले बजत सत्र में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मेरे जीवन में कालेधन की वापसी की मुद्रे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है। यह बात इन्होंने किया आधार पर कही थी? वर्षोंकि ये जनते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विश्वास दरखाये हैं। भारतीय जनता पार्टी का वसा कार्य-करताप है, वसा कार्यशीली है, वसा उनकी विवारण्यारा है, उससे ये विकिप्र कहे हैं। इसी आधार पर इन्होंने ये बात कही थी। इन्होंने सर बात कही थी। इसकी कीमत भी इनको तुकानी पड़ी। अभी इस एवरपैशन में उनको नहीं दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ठिक्काई। सही बात कहने का ढौसता बहुत कम लोगों में होता है।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा कालेधन का था। सारे देश में यह कहा गया था कि छम बहुत जल्दी इसको वापस लाएंगे। यह भी कहा गया था कि कालेधन के आगे से

देश की सारी समस्याओं का समाधान होगा, इतनी बड़ी रकम आएगी कि हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से हो जाएगा। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारा उंफ़ास्ट्रॉवर बन जाएगा। हमारे नौजवानों को शेज़ार मिल जाएगा और बहुत सारी बातें कही गई थीं। तो वे ने यही सपना देखा और आशीर्य जनता पार्टी ने यह सपना देश की जनता को दिखाया था। तो वे ने यही दिन इंतज़ार किया और अब छह महीने हो चुके हैं। तेहिन अभी तक उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। लोग बेतैन हैं कि आशिर्य हमारे प्रधान मंत्री को वया हो गया है।

अभी सलीम साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शाश्वत अपने शाश्वत में कहते थे कि उनका 56 इंच का सीना है। मुलायम शिंह जी से उन्होंने कहा कि उनका 56 इंच का सीना है। आज देश की जनता देखना चाहती है कि वह 56 इंच का सीना कहाँ गया? काते धन को वापस लाने के लिए वे अपने उस 56 इंच के सीने का उपयोग कर्यों नहीं कर रहे हैं?

महोदय, सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और वया हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि विदेशों में जमा ब्लैक मनी की जाँच का मामला वह सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकती, वर्योंकि, इस मामले में सरकार का खैया विषयानीय नहीं है। अदालत ने कहा कि सरकार विदेशी खाताधारियों की जाँच करने का काट न करें। वह तो बस उनके नामों और खातों की लिस्ट अदालत को सौंप दें, वाकी काम अदालत खुद करेगी। औपचारिक रूप से यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ़ एक टिप्पणी है, तेहिन जहाँ तक काते धन के प्रति सरकार के खैये का प्र०न है, इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को एक मुकम्मल फैसला ही समझा जाना चाहिए। एनडीए सरकार भले ही खुद को गंगा की तरह पवित्र बताने में जुटी हो, तेहिन अपनी मौजूदगी के सिर्फ़ पाँच महीने में वह न्यायालय की नजर में अपनी साख खो चुकी है।

महोदय, अंगर गवर्नरमेंट को अपनी जवाबदेही का जरा भी अल्पासार है, तो ब्लैक मनी के बारे में उसे ईमानदारी बरतनी चाहिए और अपनी तरफ से इस बारे में जो कुछ भी वह कर सके, उसे वह करने में जुट जाना चाहिए। समय का अभाव है, अन्त में मैं बीजेपी के तो वे को उर्दू का एक शेर सुनाना चाहता हूँ-

"कि तुम आसमाँ की बुलन्दी से जल्द लौट आना।

हमें जर्मी के मसाइल पर बात करनी है।"

\*m06

**श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) :** महोदय, विदेशों में जमा काते धन को वापस लाने के लिए जो वर्ता सदन में हो रही है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली ठत की ओर से इस वर्ता में शामिल हो रहा हूँ। यह वर्ता पिछले बहुत बारों से चल रही है और मैं समझता हूँ कि यह बहुत अभीर मामला है, वर्योंकि, काता धन केवल देश की अर्थव्यवस्था को ही लाइन से नहीं बिलाता है, बल्कि यह देश में और भी बहुत सारी प्रॉलेटर्स खाड़ी करता है। इसके कारण बेहोजारी की प्रॉलेटर्स खाड़ी होती है, अन्य कई तरह की सामाजिक प्रॉलेटर्स खाड़ी होती हैं और इससे देश की सारी स्थिति लड़खड़ा रही है। सब कुछ होते हुए भी जो आज देश गरीब है, मैं समझता हूँ कि उसका एक बड़ा कारण यह काता धन भी है। जब देश आजात कुआ था तो अमीर और गरीब का फासला बहुत कम था। आज अमीर और गरीब का जो फासला बढ़ा है, उसमें इस काते धन का भी बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूँ कि आज देश के सभी जेताओं को इस मामले को अभीरता से लेना चाहिए कि काता धन कैसे पैदा होता है और वे कौन तोग हैं? ये बहुत थोड़े लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी पहचान नहीं हुई है। आज जो इस छाउस में वर्ता हो रही है, मैं तो यह समझ रहा हूँ कि जैसे सौंप तो निकल गया है और तकीर को पीटा जा रहा है। ऐसी बातें अखबारों में आयी हैं, आपको भी मालूम होगा कि जब इस देश में काते धन की बात शुरू हुई और बैंकों की शर्तें तागूँ की गईं तो काता धन पैदा करने वाले लोगों ने अपना पैसा विदेशों में रख दिया। जब विदेशों में से पैसा निकालने की बात हुई तो उन्होंने अपना पैसा रिटैल एस्टेट में लगा दिया। जब गोदी साहब की सरकार के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो पालिश किया, विपक्षी पार्टी के कई ऐसे कठीर हैं, मंत्री हैं, जिनका अखबारों में नाम आया, उनके बैंक अकाउंट्स की लिटेंस आर्टी, उन्होंने पैसा निकाल दिया और बाद में ऐफिडेपिट दे दिया कि हमारा तो कोई अकाउंट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सौंप तो निकल गया और अब लकीर पीटी जा रही है। इस बात को अभीरता से लेना चाहिए। पहली बात यह है कि विदेशों में जो काता धन पड़ा है, वह किसी रूप, उसूल और शर्तों के तहत ही आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब हमारे मित्र खड़गे जी बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्वर्य हो रहा था कि वे सरकार को बोल रहे थे कि आप तोगों को गुमराह न करें। जो लोग अपनी सरकार के समय 24 घंटे में 24 बार देश के तोगों को गुमराह करते रहे, आज इनको कहते हैं कि गुमराह न करें। ये शजनीतिक बातें करने के बजाय इसको अभीरता से लेना चाहिए कि यह धन कैसे वापस आ सकता है।

दूसरी बात में कठना चाहता हूँ कि देश में जो काता धन पड़ा है, उसको भी सामने लाना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। हमारे नौजवानों को नौकरियों की ज़रूरत है और बैंक वाले पैसा नहीं देते, पैसा होता नहीं है। जो पैसा बाहर पड़ा है, जब वह आएगा तो देश की मरठ होगी। यह केवल पैसा वापस लाने की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो देश का पैसा बाहर ले जाते हैं, काता धन बनाते हैं, वे देशदूषी हैं, वे देश के दुश्मन हैं। इसको इकोनॉमिक ऑफिन्स तो माना ही जाए मगर उन पर किसीने अंफिन्स भी होना चाहिए ताकि आगे से ये काता धन बनाने वाले लोग हीसला न कर पाएँ। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कठन करता हूँ कि मोदी साहब की सरकार ने जैसे सरकार बनाते ही एसाईंटी बनाई और आगे कठम बढ़ाए, सरकार की नीति और नीताएं पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं यही निरेदन करना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने शुरूआत की है, इसको आगे बढ़ाया जाए और सरकारी सेवा काम दिया जाए ताकि देश में यह जो काते धन की बीमारी है, इसको सदा के लिए खत्त कर दिया जाए।

\*m07

**श्री राजेश रंजन (मधेपुर) :** सामाप्ति महोदय, हमारे मित्र अनुराग जी यहाँ नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने कठन कुछ बातें कही थीं। अनुराग जी ने कठन कठा था कि हमारी सरकार न्याय की क्षमीती पर खड़ी है। पुनः मुझको वह 56 इंच का सीना याद आ गया। नौ साल नुजियत में लोकायुक्त की बढ़ाती होना 56 इंच के सीने का नमूना है। खोदा पढ़ाड़ निकली चुहिया! फिर चुहिया की चुहिया! यहि आप देश को न्याय देने की बात करते हैं तो कम से कम इंसानियत और अपने घर को तो न्याय दे दीजिए जिसके बारे में अब मुझे कुछ नहीं कहना। पूरा देश जान रहा है कि किसको न्याय देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, लेहिन जो बात यहाँ पर हो रही है, उसके पहले हम कठना चाहेंगे कि हम सब लोग अपनी अंतरात्मा में देखें। जो इंटर्व्हेट पर देते हैं कि 25 ज़ज़ार कठोड़ रूपये या ज़ज़ारों कठोड़ रूपये आपके प्रवार-प्रार यंत्र पर तोगे, ये किनके पैसे लग रहे हैं? हमारे मैं सब नंगे हैं। हम लोग यहाँ एक दूसरे को गाती देने वैठे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। हर डात पर उत्तू बैठा है, अंजाम-ए-नुलिस्तां वया होगा?

**एक माननीय सदस्य :** आप कठना वर्ता चाह रहे हैं?

**श्री राजेश रंजन :** हम साफ कठना चाह रहे हैं कि आप और हम, यहाँ वैठे हुए जो लोग काते धन पर वर्ता कर रहे हैं, हम पहले बाहर नहीं जाएँ। सब तोगों ने कठ दिया है और हम भी कठना चाहेंगे कि जिन बाबाओं के बारे में आपका ओपीनियन बहुत अच्छा है, उनका काता धन आप कब जिकावेंगे, उसके बारे में भी आप कठनों की कृपा करें। मंदिर के तहस्त्राने में किनके-किनके कठनारों-तारों कठन करते हैं, तब तक जीती और रिजर्व बैंक ने पार्टीसिपेटरी नोट के द्वारा रस्तूक एसरेंज और रीयत एस्टेट में नियेश होता है और यह यही से काता धन बनता है।... (व्यवहार) मैं कुछ नहीं कठना चाहूँगा। पार्टीसिपेटरी नोट के द्वारा रस्तूक एसरेंज और रीयत एस्टेट रेप्रेशन सर्किल आफ ब्लैक मनी के लिए सेवी और रिजर्व बैंक ने पार्टीसिपेटरी नोट को बंद करने के लिए कठन की जाता धन बनता था। यही दिन इंतज़ार किया जाएगा।

आपके पास सूरी हैं। सूरी के बारे में कुछ कठनों की ज़रूरत नहीं है। आपका नेता वर्ता कर सकता है।... (व्यवहार) मैं कुछ नहीं कठना चाहूँगा। पार्टीसिपेटरी नोट के द्वारा रस्तूक एसरेंज और रीयत एस्टेट एसेंजेंसी से काता धन बनता है।... (व्यवहार) रेप्रेशन सर्किल आफ ब्लैक मनी के लिए सेवी और रिजर्व बैंक ने पार्टीसिपेटरी नोट को बंद करने के लिए कठन की जाता धन बनता था। यही दिन इंतज़ार किया जाएगा।

आपसे कहा गया है।

तीसरी बात यह है कि दिलेखों से जो काता धन शीरथ स्टेट में लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो आप शीरथ स्टेट में छूट देने की बात कह रहे हैं, वहा यह काता धन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, वहा आपकी सरकार काते धन को बढ़ावा नहीं दे रही है? संस्थागत नियेशक एफआईआई के माध्यम से भारत में जो पैसे आ रहे हैं और भारत से जो पैसे जा रहे हैं मैं इस बारे में आपसे पूछूँगा कि इनके बारे में आपकी वहा शय है मुझे बहुत ज्यादा कठने की जरूरत नहीं है वर्तोंकि सतीम साहब ने जिन बातों को उद्धृत किया है, मैं उनकी बातों से और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बातें कही हैं मैं उनकी बातों से सहजता हूँ लेकिन मैं एक बात जरूर कठना वाला हूँ कि धमेशा कानेस को गाती, यूपीए को गाती, आप गाती देने के लिए नहीं हैं आप व्हैक मनी बाटुर से ताएं या कहीं से भी लाएं, आपने वायदा किया है कि डिंदुस्तान के एक गरीब को 15 लाख रुपए मिलेंगे। आप वह 15 लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप पैसा कठन से ताएं या नहीं लाएं, इसे आप देखें। जो सरकार ठालातों, विचौलियों, मुझे आश्वर्ष है कि मुंगेरी लात का दूसरी सपना आपने दुनिया को दिखाया है इतना बड़ा सपना, नटवर लाल और वाल्स शोभजात भी आपके सामने फैला हो गया, मैं आपसे कठना वालूँगा कि आपने जिन सपनों पर डिंदुस्तान के कियानों को, नौजवानों को, गरीबों को लगा है, लूटा है, उसके बारे में मैं सिर्फ़ एक ही बात कठना वालूँगा - "शमपात ने तूटा कबीर के नाम पर, आशा राम ने तूटा छिरिओम के नाम पर, बीजेपी ने तूटा शम मंदिर के नाम पर और मोदी जी ने तूटा छठ दिन के नाम पर।" मुझे बहुत कुछ नहीं कठना है मैं आपसे सिर्फ़ एक ही बात कठूँगा कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपकी नीति और नीति दोनों में फर्क है। आप अपने प्राकानंत्री जी से जरूर कहें कि यदि उनका 56 इंव का सीना है, तो निष्ठित रूप से इस देश के भीतर जो काता धन है जो डलाल, विचौलिया, भ्रष्ट गेता, कोरपोरेट घरानों की जो तात्परत और धारागत है, उसे समाप्त करने का सबसे फलो प्रायास करें। देश के भीतर के कातो धन को योके का प्रायास करें और जो शीरथ स्टेट के नाम पर अलन-अलग, एफआईआई के नाम पर या एफआईआई के नाम पर जो देश में पैसा लाने की बात हो रही है और आप पैसे से देश में दृश्याणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाए जा रहे हैं, आपको कोई मैनडेट नहीं मिला है। आप शिवसेना के साथ होते, तो आपको पता चल जाता, महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाते। आपने शिवसेना से अलग हो कर, विधार और यूपी का योट लेकर सरकार बनाई है। यहां आपने गैर जाटों का नाया देकर सरकार बनाई है। आपने अपने बल पर सरकार नहीं बनाई है, आपको कोई मैनडेट नहीं मिला है। मैं आपसे यह कठना वाला हूँ कि आप इस देश के सबसे बड़े देश के नौजवानों, गरीबों को लगा है। आपको देश के 120 करोड़ लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आपसे कठना वाला हूँ कि नेशन्दू मोदी जी इस जन्म में काता धन वापिस नहीं ता पाएंगे। जब अमरीका काता धन वापिस नहीं ता पाई, अमरीका जब समझौता कर सकती है तो नेशन्दू मोदी जी, जिस अमरीका जाने के लिए आप परेशान हैं, तो आप कहं से काता धन ताएंगे। यही सही बात है और यही सही बात है।

\*m08

**श्री भगवंत मान (संग्रहर):** आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज एक बहुत लंबी गंभीर विधाया पर बहर वाल रही है, तोगों से जो वायाटा किया गया था, इस मुद्दे पर पार्टीयामें वर्ता करने का वायाटा नहीं किया गया था। सौं दिन के शीतर पैरों पापस लाने का वायाटा किया गया था। अब कहा जा रहा है, उस वर्ता के लिए तैयार हैं। कर्दीं एक शी बुनावी आँखों में बी.जे.पी. के किरणी एक शी नेता ने कहा था कि छाँ घोट दीजिए, छाँ यों दिन के शीतर-शीतर संसद में कालेघन पर वर्ता करवाएंगे। आपने कहा था कि कालाघन वापस लाएंगे। वर्ता तो आडवाणी जी ने दिवानब, 2011 में करवा ली थी। कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो जवाब दिया था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इसलिए कालेघन को वापस लाने में दिवकर्ते आ रही हैं। वही जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में बी.जे.पी. ने दिया है। सिर्फ कुर्सियों पर संसद में जो मानवीय सदस्य बैठे हैं, वे बदल जाते हैं, लैपट वाले राइट आ जाते हैं, राइट वाले लैपट आ जाते हैं। तोगों की फिरमत नहीं बदलती। आप एक-दूसरे पर इत्तजाम ताना रखे हैं, 2011 में यह कहा था, 2009 में यह कहा था, तेकिन आप तोगों ने तो आंकड़े दे दिए थे कि 15-15 लाख दूर भारतीय के साथे में आ जाएगा। जब आपने जनघन स्कीम में तोगों के साथ खुलाए तो तोगों को खुशी दुर्द कि शायट इन्हीं खातों में 15-15 लाख आएगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, यह तो बहुत मुश्किल है। पहले आपने आठ सौ नामों की बात की, पिर सात सौ की बात की, उसके बाद आपने 627 नाम लिए। वह 73 नाम तौर से हैं, जो आपने लिया लिए? अब राधा टिम्बलू का नाम आ रहा है, जिसकी कम्पनी इंटिलगेंट माइनिंग में लौक टिरेट है। उसका नाम उस लिस्ट में है। उसने एक करोड़ 18 लाख रुपए बी.जे.पी. को बन्दा दिया और 65 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को बन्दा दिया। इसका मतलब आप दोनों पार्टीयों को पता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। आप उनसे बन्दा लेते हैं। पहले अपना काला मन साफ करो, पिर आ पाएगा कालाघन। यूपी और श्री की गवर्नर्मेंट मुझे लग रही है, वित मंत्री, श्री अरुण जेटली जी का जो कल ब्यान था, वह तो मुझे लग रहा है विद्यमान सालब बोल रहे हैं। आम जनता पूछ रही है कि छाँगा पैसा, छाँगी मेहनत का, छाँगे खुन-परीजों की कमाई का पैसा जो विदेशी में पड़ा है, वह कब आएगा?

### **16.56 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)**

मैं इसी बात पर एक छोटी सी कविता लोक कर बैठ जाऊंगा। "कालोधन के बारे में कहा गया थी। जे.पी. की ओर से, कालोधन का मुद्दा उठाया गया पूरे जोर से, कहते थे हमारा तो बहुत मजबूत इशारा है, सौ दिन के अंदर-अंदर कालाधन वापस लाने का बायादा है, सरकार जी, सौ दिन तो कब के निकल गए, वर्षा योग गुरु के साथ आपके इशारे भी पिछले गए, पूरे देश की जनता के मन में यह सवाल है, अनगंत मान का भी यही ख्याल है कि कब खुलने वाला रियस बैंक का ताला है, जल्द अच्छे दिन तो नहीं आए, यह बता दो कालाधन कब आने वाला है।"

\*m09

**श्री निशिकान्त दुबे (गोडारा) :** अध्यक्ष मर्लोटर्या, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धनरावाद देता हूं "अजीब दारतां हैं ये, कहां शुरू, कहां खत्म।" Koenraad Elst की एक बहुत अच्छी किताब है, Negationism in India. हिन्दुस्तान के आदमी को भूतने की बड़ी वीमारी है, बड़ी जल्दी-जल्दी भूत जाते हैं। तारीक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, डमने कठा कि नहीं आएगा। यह एक रिपोर्ट है, तिर्यौस्टाइन जो बैंक है, उस बैंक की एक रिपोर्ट है। उस बैंक की रिपोर्ट में एक बड़ा अच्छा जिक्र है कि रुप्य स्पूनशी जी पीआईएल में उन्होंने कोट किया है - He said: "Member of Parliament Nishikant Dubey had disclosed in the House how funds of Leelavati Hospital were being siphoned and used by these individuals to buy stakes in banking institutions." उन्होंने और वर्चा-वर्चा कठा, मेरे आपण को कोट करते हुए उन्होंने फैन सी बात कही। उन्होंने कठा - "Some of the individuals are on the Board of Directors of the ING Vysya Bank and are co-promoters of IndusInd Bank, trustees in the State supported charitable trust, Leelavati Hospital and even own a Cricket Team in the Indian Premier League, the Kochi Team."

**17.00 hrs**

कोटिय टीम के मातिक कौन थे, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपीए सरकार के मंत्री थे और मेरा ही एडजर्नेंट गोशन था, जिसके बाद उस समय की सरकार ने उनको मंत्री पद से हटा दिया। नीरा राडिया का केस दुआ। नीरा राडिया का मुद्दा इस पार्टियांगेंट में वर्ष 2009 में मैंने उठाया था। इसके बाद दूर जी का इतना बड़ा घोटाला हो गया। तारिक आई, इस देश में भूतने की बड़ी बीमारी है। तीन साल में छी ये भूत गए। 7 अप्रैल, 2011 का सुप्रीम कोर्ट में दर्ख सुनिश्ची का इंटरव्यैशन था। उनकी तरफ से रामजेमलानी, प्रूंसांत भूषण, शांति भूषण आदि लोग एपियर हुए थे। उसके बाद एसआई का इस देश में निर्माण हुआ था। एसआई के निर्माण में जो अभिका है, उसमें 15वीं लोक सभा के एक मेंबर ऑफ पार्टियांगेंट की भी अभिका है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए।

मैं मुतायम शिंग यादव जी को देख रहा हूं। याद नारों की बात चाह रही है, बड़े नारों की बात चाहती शिकमगतूर का बुनाव हुआ। तब कठा गया - एक शेरीनी, जी तंगूर, शिकमगतूर, शिकमगतूर। कौन है तंगूर? मुतायम शिंग यादव जी, जब आप बनत में बैठते हैं तो मुझे आपके ऊपर बड़ी ढंगी आती है ... (ल्याप्तान) एक शेरीनी, जी तंगूर, शिकमगतूर, शिकमगतूर। तंगूर कौन है?

गवर्नरी छात्राओं का इस देश में नाया आया। जब वर्ष 1969, 1970, 1971 में बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था, योंता का नेशनलाइजेशन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी की नेता ... \*...(त्वरितान) जो

अब नहीं हैं, उनका इस देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं उनका बहुत आठर करता हूं। वह बोलती थी कि जैसे ही बैंक का नेशनाइजेशन हो जाएगा, सारे नरीबों के यहां पांच-पांच छजार रूपए चला जाएगा। उस वक्त पांच-पांच छजार रूपए महत्वपूर्ण थे। यहि कॉल का नेशनलाइजेशन हो जाएगा, इलेवशन कैपेन में उन्होंने कहा है, मैं सब कुछ उठाकर लाया हूं। ... (व्यवधान) इलेवशन कैपेन में उन्होंने कहा ... (व्यवधान) मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम मत लीजिए।

â€|(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं जाएगा।

â€|(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : जब आपकी बात होनी, तब आप अपनी बात रखिएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कह दिया है कि नाम नहीं जाएगा।

â€|(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : वर्ष 1971 में नरीबी छटाओं के नारे पर आए या नहीं, वर्षा इसमें भी कोई दो गत हैं? तेंदुलकर कर्मी की रिपोर्ट आरी है कि चालीस परसेंट लोग आज भी नरीब हैं। नरीबी छटाओं के नारे के बाद वर्षा कांग्रेस पार्टी ने यह जवाब दिया? वर्षा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उससे पूछा कि नरीबी छटी या नहीं? ... (व्यवधान) चालीस परसेंट लोग अभी भी नरीब हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकान्त जी, आप बोलिए।

â€|(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, आपने भी इस सदन में खड़े होकर कहा कि काली छतरी लेकर लोग आ रहे हैं। आज मैंने देखा कि काला शॉल लेकर आ रहे हैं। मेरे मन में आया कि इस डिबेट में काले धन पर ये सारे तोग परिवर्त वर्षों से गए हैं? कर्मी का ईंट, कर्मी का रोड़ा, आनुमती ने कुनबा जोड़ा, ये सारे कुनबे एक साथ एकत्रित वर्षों से गए हैं? मैंने इस पर बड़ा ध्यान दिया। यह बिना मौसम बरसात हो रही है। तंदन की तरफ लोग छतरी लेकर यहां आ गया है। अभी गर्मी है, काला शॉल लेकर आ गए हैं।

जन-धन योजना में हैं कि छजार करोड़ रुपए आ गए। इसमें सभी नरीबों का खाता खुल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मेंक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। वैकेंच्या जी ने अभी बहुत सारी बातें कर्मी। प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, तंदन जा रहे हैं, विष्व में जा रहे हैं, आस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सभी जगह उनका स्वागत हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बेस कर्मी न कर्मी हितता हुआ नजर आ रहा है।

अभी जो रिजल्ट आए हैं, उसे आप अन्वर देखेंगे तो कांग्रेस क्षियाणा टॉस कर गर्वी, महाराष्ट्र टॉस कर गर्वी। मुतायम रिंग जी को पता है कि जितनी सीटें आपने वाई-इलेवशन में जीती हैं, बहुजन समाज पार्टी के नई खड़ा होने के बाद आपको उतनी सीटें मिल गयी हैं। आपकी भी जमीन हिती हुई है। आरजेडी वाले यहां बैठे हुए हैं। ... (व्यवधान)

श्री मुतायम रिंग यादव : आप खड़ा करके देखा लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आरजेडी का जेडीयू के साथ उन सीटों पर समझौता हो गया, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं। जब जनरल इलेवशन आएगा, तो आपको भी खबर आ जाएगी कि आपकी 121 सीटें हैं, उनमें से कितने का बंतवारा करेंगे? सभी आटमी अपना पॉलिटिकल बजूट बचाने के लिए, वर्षोंकि किसी के पास कोई मुहा नहीं है और प्रधानमंत्री की इमेज इतनी बड़ी हो रही है, तो इन सभी ने गिलकर सोचा कि तिनका-तिनका एक करके, डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि कोई मुहा नहीं है तो बैंक मरी के मुहे पर बातचीत कर ली जाए। ... (व्यवधान)

महोदया, मुहा कितना डैरिल हुआ? डिबेट का लेवल आप देखिए, कौन चौर, कितना चौर? बड़ा अच्छा आपने दिया है, खड़गे साफ्ट कोट कर रहे थे कि बैंक का एनपीए हो रहा है। रूपीकर महोदया, छ: महीने में इस सरकार ने तो एन.पी.ए. नहीं कर दिया, साके छ: लाख करोड़ रुपए का एन.पी.ए. है, इस सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपए राइट-ऑफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजोंके बाद तीन लाख करोड़ रुपए माइन्स में एवसपोजर, खात्म हो रहा है। यार करोड़ रुपए के पावर प्लांट बने हुए हैं, जो खात्म होनेवाले हैं और तीन लाख करोड़ रुपए बेसील नॉर्स के आधार पर सरकार को बैंकस में इंजिन बनाना है। इसका सतर लाख करोड़ रुपए टोटल एवसपोजर है। ... (व्यवधान) मेरे पास पूछे तिष्ठं हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा बास-बार नहीं होना चाहिए। कृपया आप अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Nishikant Dubeyji is saying.

(Interruptions) â€|\*

श्री निशिकान्त दुबे : जिन सौ कंपनियों को आपने दस साल में लोन दिए हैं, जिनकी बुरी स्थिति है, जोकि घाटे में हैं और यहि इस सिद्धांशन में बैंकस कोलैप्स कर जाएंगे तो दोष किसको, कौन चौर तो "टेक्ना चौर", यह एन.डी.ए. ने कर दिया। आपने दस सालों में देश का कबाड़ा कर दिया, इसको आपको समझना चाहिए। मतिलकार्नुज खड़गे, साफ्ट ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहा - छमारे नेता ने यह कहा, छमारे नेता ने यह कहा। मैडम सोनिया जी बैठी लुई हैं तो मुझे बहुत सुनिया है। इन्होंने 27 अक्टूबर, 2009 में, मैंगलोर में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग एड्रेस की, उसमें उन्होंने कहा -

"If elected, would work to bring the black monies illegally stashed away by Indians abroad."

पांच साल में कितना पैसा आया, इसके बारे में यह आपने पूछा? ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, कहा कि रामदेव बाला के बगल में प्रधानमंत्री जी ने मूँही छिता दिया, इसलिए वह भी दोषी हैं। ... (व्यवधान) यह वर्ष 1991-92 का मनगोळन रिंग जी का बजट है। मैं सब तीजे ते कर आया हूं। उन्होंने बजट में कहा है -

"Nobody can deny the existence of large scale tax evasion, both in terms of income and in terms of wealth. Unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months, Government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such delinquency. Before coming down heavily on tax evaders, I would like to give them a last opportunity to come clean. The black money so mobilised will be utilised for the achievement of social objectives such as slum clearance and low cost housing for the rural poor."

यह उन्होंने वर्ष 1991 में कहा है। वर्ष 1991 से लेकर 23 साल तक कितने स्लम्स बलीयर हुए और कितने रुपल लाउंसिंग हो गई, सरकार को यह बताना चाहिए। ... (व्यवधान) यह मनगोळन रिंग

जी का बयान है। ... (व्यवधान)

ए.पी.सिंह साहब के बारे में वैकल्पिक नायदू जी बोल चुके हैं ... (व्यवधान) इसी में, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस अल्पवल ट्रांसपरेंसी का एल.के. आडावाणी जी के संबंध में जिक्र किया गया, प्रणव मुखर्जी साहब ने "व्हाइट पेपर" में लिखा है -

"During the recent winter session of Parliament, Union Finance Minister Pranab Mukherjee had promised to bring out a white paper on black money. Quoting figures of Global Financial Integrity, he had said that from 1948 to 2008, about \$213 billion was stashed away by Indians in foreign banks. "At the current value, this would amount to \$462 billion," Mukherjee had said."

आप एल.के. आडावाणी साहब की बात करते हैं, यह प्रणव मुखर्जी साहब ने खुट कहा है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपने तीज को कैंसरस बना दिया है। महिलाकार्जुन खडगे साहब जे कहा है कि यह आजारी के पहले से है। यह सही है। वर्ष 1936 में "अल्पवल कमेटी" की रिपोर्ट बनी। मोहनमद सलीम साहब ने "वांगतू कमेटी" की रिपोर्ट का बड़ा अच्छा जिक्र किया है। "वांगतू कमेटी" की रिपोर्ट में वह कहा गया है कि वर्ष 1970-1971 में, इस देश की वित मंत्री श्रीमती इंदिरा जी थीं। इंदिरा जी ने कहा कि "ब्लैक मनी" एक बड़ा विषय है, इसलिए "वांगतू कमेटी" बना देते हैं। "वांगतू कमेटी" की फाइलिंग में वह आया? उसने सबसे पहले कहा -

"Thirteen years ago the Wanchoo Committee Report depicted the phenomenon as a cancerous growth in the country's economy which, if not checked in time, will surely lead to its ruination."

जब आपने इसे कैंसर बना दिया तो आप चालते हैं कि कैंसर का इताज थी। दिन 1971 की वांगतू कमेटी की रिपोर्ट है जो श्रीमती गांधी ने बनाई। र्पीकर मछेदया, कांग्रेस की एक आटत है कि जब इनकी इच्छा होती है एक कमेटी बना देते हैं। उससे पहले एक सांतन कमेटी बनी... (व्यवधान) सांतन कमेटी कहती है कि इसके बढ़ते से शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जब दीजे बहती गई, वांगतू कमेटी बनी, वोपड़ा कमेटी बनी, कालोदकर कमेटी बनी, कालोदकर कमेटी बनी। जब छाजार कमेटी बन गई तो जिस तरह अभी एसआईटी के बाद तीन एजेंसियों को दे दिया, मठावास साहब ने बताया कि एसआईटी वयों नहीं बनी। इसके बाद इन्होंने शंकशावार्य, शाजा वर्तैया इन सबके नेतृत्व में, जब 1980-81 में फिर से श्रीमती गांधी आई तो एक कमेटी की रिपोर्ट आई जो 1985 में इस पालियामेंट में लाली गई। उसने उन्होंने कहा कि किस कारण ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ब्लैक मनी जो स्ट्रॉवर औंफ टैपस इपेजन है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार की कमेटी की रिपोर्ट है। 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्हें इस कमेटी की रिपोर्ट दी गई। 1983 में श्रीमती गांधी ने कमेटी बनाई थी, मैं सरकारी कमेटी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किस कारण ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ब्लैक मनी जो स्ट्रॉवर औंफ टैपस इपेजन का नहीं हो रही है, कंट्रोल औंफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, जनरल टॉज़ एंड ऐन्युलेशन का पालन नहीं हो रहा है, पोलीटिकल फाइंडेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नवनींस स्टैंडिंग की रफेल और एकाउंटेंटिव पूरी नहीं हो रही है, स्टैन्डर्ड औंफ पब्लिक मॉर्टिंग रात्म हो रही है और इनपोलेशन रात्म हो रहा है। आपने इसके बारे में कोई एवशन नहीं लिया। 1985 से आप कितनी बार सरकार में आए। 1985 में आए, 1991 में आए, 2004 में आए, 2009 में आए... (व्यवधान)

मेरे कुछ पूँज हैं कि एसआईटी वयों बनी। एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट आया है। मैं उसे भी कोट करूँगा कि इस देश में इस तरह का माहौल वयों बना। माहौल इसलिए बना कि ब्लैक मनी जनरेशन के लिए जो कानून है, उसे कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। ब्लैक मनी किस-किसे जनरेट हो रही है। व्हाइट पेपर कहता है कि आउट औंफ बुक ट्रांजैक्शन हो रही है, पैरलेट बुप्स औंफ एकाउंट्स मेनेटेन हो रहे हैं, मैनिपुलेशन औंफ बुक एकाउंट हो रहा है, मैनिपुलेशन औंफ थेल्स रिपोर्ट हो रही है, अंटर रिपोर्टिंग औंफ प्रोडक्शन हो रहा है, मैनिपुलेशन औंफ एकाउंट्स रिपोर्ट हो रही है, अंटर मैनिपुलेशन औंफ एकाउंट्स हो रहा है, मैनिपुलेशन औंफ कैपिटल हो रहा है। यह आपका ही व्हाइट पेपर कह रहा है यानी शिकायी आएगा, जाल बिछाएगा, इस जाल में कोई फ़ंसान नहीं। लैंड एंड रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छा बताएगी। बुलियन एंड जैलरी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। फाइनैंसियल मार्किंग का ट्रांजैक्शन हो रहा है। पहिला प्रैक्टिकल मॉर्टिंग जिसमें करणशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपने कोई एवशन नहीं लिया। आप केवल बताते रहे कि ऐ-ऐ-कॉर्ज़ हैं। इन्हें शेषने के लिए आपने कौन से उपाय किए... (व्यवधान) छें अभी तः मठीने हुए हैं... (व्यवधान) इन्फार्मेट ऐटरट में वहा हो रहा है, एवस्टर्नेट ट्रेड में वहा हो रहा है, ट्रस्ट में पैसे डालो जा रहे हैं। जब कोई एवशन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब यह डाला गया तो मेरे कांग्रेस पार्टी से कुछ पूँज हैं... (व्यवधान)

दूसरा अल्पी का मामला ऐसा है कि इनकम टैपस इपार्टमेंट मानता है कि उसके पारा 71 छाजार करोड़ रुपये फ़ंसे हुए हैं... (व्यवधान) दूसरा अल्पी कौन है? दूसरा अल्पी को कांग्रेस पार्टी ने कैसे बताया। इस सरकार ने दूसरा अल्पी को तीन-तीन पासपोर्ट दिए। वह तीन पासपोर्ट रखने के जुम्म में जेल में जाता है। उसके बाद उसे इमीलिएटली अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मेरा कहना है कि वहा उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए किसी सरकार ने इजाजत दी? वहा पुणे और मुम्बई की पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई? इंस्पैक्टर क्राइम आनुप्राप्त जो पुणे में बेरड थे, उन्हें किस आधार पर ट्रांसफर किया गया? ईडी ने उन्हें टिस्म्बर, 2007 में जो नोटिस दिया, उसके बारे में सरकार ने वहा किया?... (व्यवधान) मैं दूसरा अल्पी की बात कर रहा हूं कि एसआईटी वयों बनी... (व्यवधान) उसका संबंध युसुफ लकड़वाला से था या नहीं? उसका संबंध अबना खांशेही से था या नहीं? मैडम सोनिया जी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लिटो के साथ उसके संबंध थे या नहीं? प्राकरण को उसने फ़ंड दिया या नहीं? जब आप दूसरा अल्पी जैसे तोनों को बताने का प्रयास करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैंट आता है। उसने दूसरा अल्पी को बड़ा अच्छा कोट किया है। दूसरा अल्पी को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है जिसके लिए आप एसआईटी नहीं बनाने के लिए अड़ गए... (व्यवधान) छम सब बतायेंगे। ... (व्यवधान)

"The bank in which the money has been stashed by Hasan Ali Khan was UBS, Zurich. The needle of suspicion has to be inexorably turned to high level political interference and hindrance to the investigation." यह मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जिसके आधार पर एसआईटी बनी है। वह कह रहा है कि पोलिटिकल टंकिंग्स हो रहा है, दिनदूनस डाला जा रहा है। "The said bank, it was submitted, is the biggest or one of the biggest wealth management companies in the world. The petitioner also narrated the mode and the manner in which the United States had dealt with UBS with respect to monies of American citizens secreted away with the said bank." यह सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आप यूएस की तरह कोई काम करने का प्रयास करें। ... (व्यवधान) आप दूसरा अल्पी को बंद करें, आप क्रेडिट रखीज़ और यूटीएस जैसी जो संस्था है, उसे करें। ... (व्यवधान) मैं यह नहीं कहता मैंने कोट नहीं किया कि प्रतिभा पाटिल जी ने वहा कहा? मैंने यह नहीं कहा कि प्रधान मंत्री जी ने वहा कहा, इसी पार्टिमेंट में वहा कहा? ... (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि मदात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले लोग आप पर दूसरे और दूसरे के बाद आपको काम नहीं करने देंगे। जब आप काम करके जीत जायेंगे, तो कुछ बातें ढोंगी। ... (व्यवधान) यह सरकार कुछ काम करने का प्रयास कर रही है, ब्लैक मनी को ताने का प्रयास करती है। बंद मुद्दे से कोई छात नहीं मिलाया जा सकता। कहीं न कहीं रसता निकालने की बात होती है। यह सरकार अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोशो-सारेश से, जो भी ताकत है, जो भी बुद्धि है, डीटीए का साल है, उसके लिए सैन्फ्रॉन्ट रेन्यू रिटार्जरेंट जाये हैं। उन्होंने कहा है कि कैरेल वही नहीं, जो एकार्सीरी से नाम आये हैं। यानी सैन्फ्रैंटराइन बैंक से आये हैं, उतना ही नहीं, इसके अलावा दूसरे जो इनकम टैपस देते हैं, वर्तोंपरि जिस बड़ी अल्पी कोट किया गया है, दिनदूनस के इतिहास में इतना कैश किसी भी सरकार ने किया था। उसकी बड़ी छेंडे में नहीं कपड़ा है, वाहे ब्लैक मनी अंटरनेट जनरेशन का सवाल हो, वाहे ब्लैक मनी आउट साइड जनरेशन का सवाल हो, यहि इनकम टैपस के सर्व एंड सीजर में किसी आदमी को पकड़ेंगी, तो उसका भी इनफोर्मेशन ठेगी।

**माननीय अध्यक्ष :** अब आप अपनी बात कनवरतूड कीजिए।

â€“(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुखे :** आटोमेटिक टैपस एवशनेंज आ रहा है। आप विश्वास कीजिए कि इसदा करने वालों को शांति दीजिए, काम करने वालों को समय दीजिए और भानुमती के कुनबे की तरह अपने आपको जोड़ने का प्रयास करनी जीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री बद्रुल्लीन अजमता।

आप थोड़े शब्दों में अपनी बात कहिए।

â€“(व्यवधान)

\*m10

**श्री बद्रदीन अजमल (धूबरी):** अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मैं यहां सवालों सुन करने के लिए आता हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 'उम्र-ए-दराज मांग कर ताये थे तार ठिन, दो आरजू में कर गये, दो इंतजार में' आजारी के जमाने से यह झगड़ा शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। छक्कीकत यहा है? मैं इसमें डाउटफुल हूं कि कहीं लौक भी कुछ है या नहीं और कहीं राफेंटी भी कुछ है या नहीं, मैंने राफेंट कपड़ा पहना हुआ है, यह मैं जानता हूं और लौक भाई, मेरे आसी जो कह रहे थे, वे बहुत अच्छे लेवरर हैं। यहां थेरे हुए भी सभी अच्छे लेवरर हैं। लौक कोट छर आदमी पहनता है। आसी सर्टी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए स्वेटर से छी काम चल रहा है। बहुत जल्दी जैकेट का भी जमाना आयेगा। लेकिन छक्कीकत यह है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाये। हम लोगों पक्ष के लोगों से यही कहेंगे कि भाई, इसे सीरियसली तो, नहीं तो एक आदत हो गयी है, परम्परा है कि यहां वाले आपेक्षित हैं वहां वाले आपेक्षित हैं वहां वाले अपने आपको बताने में विल्टारेंगे और मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। अब भासले का छल निकालना है, तो सब निलकर संजीदगी में बैठें और वाकई छी काते थन को, जो अंदर है या बाहर, जो काता हिस्सा हमारे अपने कपड़ों में छिपा हुआ है, उसे भी हम उजागर करने की कोशिश करें।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

\*m11

**श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिस्ट्रीज़र):** माननीय अध्यक्ष जी, ताजमहल पूरा सदन इस बात पर सम्बन्धित है कि कालाधन सार्ट्रीय संपदा है और इसका उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए। दुर्भाग्यवश कालेधन का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग, आतंकवाद जैसे तमाम शार्ट्स विशेषी कारों के लिए किया जा रहा है। हमारे सामने कालेधन के संबंध में दो बड़े सवाल और बुनौतियां हैं। पहला पूर्ण यह है कि हमारे देश में कालेधन की उत्पत्ति हो रही है, उस पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। दूसरी बुनौती यह है कि विशेषी बैंकों में जो कालाधन जमा है उसे भारत में कैसे वापस लाया जाए।

जल्द तक पहली बुनौती का सवाल है, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन करके कालेधन की उत्पत्ति पर रोक लगाना संभव होगा। हमारे देश में एक समय पर एक, तो और पांच रुपए जैसे छोटे गोटों का प्रवालन था लेकिन धैर्य-धैर्य यह समाप्त हो गया। यह जरूरी है कि छोटे गोटों के प्रवालन को फिर से शुरू किया जाए। 500, 1000 रुपए जैसे बड़े नोट, जो मुख्य रूप से कालेधन की उत्पत्ति के कारण हैं, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। 500 रुपए के गोटों की संख्या को सीमित किया जाए। आज 1000 रुपए के नोट इसका बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं, उसके चलन को रोकने पर सरकार को विवार करना चाहिए।

दुनिया के तमाम देशों में ट्रॉजेवशन ब्रेस्ट टैक्सेशन शिर्टम को लान्गू किया गया है और इसे सफल रूप से संवालित किया जा रहा है। इसी व्यवस्था को हमारे देश में लान्गू करने के लिए नीति निर्धारण के बारे में सरकार को विवार करना चाहिए। जब तक यह परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तब तक संभव नहीं होगा कि देश की सीमा के अंदर कालेधन की उत्पत्ति पर रोक लगाई जा सके। देश की 95 प्रतिशत पूँजी 10 प्रतिशत लोगों के हाथों में केंद्रित है जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, यहि ये परिवर्तन नहीं किए गए तो इसे हम कभी रोक नहीं पाएंगे और न ही देश में कालेधन की उत्पत्ति और कारोबार पर रोक लगा पाएंगे।

जल्द तक दूसरी बुनौती की बात है जो विशेषी बैंकों में जमा कालाधन देश में लाने के संबंध में है। सरकार ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता का परिवर्त्य दिया है। जी-20 सम्मेलन में जिस तरह हमारे देश के पूर्णांमती आदरणीय मोटी जी ने पूँजी अंतर्गत्वीय समूह को एकजुट करने का साहस दिखाया है, यह अपने आप में एक उताहण है। माननीय मोटी जी और उनकी सरकार जिस प्रकार 88 देशों के साथ डबल टैक्स एवाइडेंस एन्फ्रीमेंट का निष्पार्क पालन करना चाह रही है, यह भी अपने आप में सरकार की संकल्पबद्धता को साखित करता है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन में कुछ देर पहले बताया कि 26 मई को सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 29 मई को होने वाली कैबिनेट की प्रथम बैठक में एसआईटी के गठन के संबंध में निर्णय दिया गया। इसके बाद एसआईटी का गठन भी हुआ। जून में 627 लोगों के नाम की सूची भी एसआईटी को सौंपी गई। अब एसआईटी द्वारा जांच की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का छताक्षेप नहीं है। इनके प्रयासों के बावजूद जो कार्य पिछले साठ वर्षों में तमाम सरकारों ने नहीं किया और अब मोटी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि छ: माह के अंदर सरकार यह काम कर लेगी तो यह छायाचाप है। ऐसे कारों के लिए सरकार को नियमित रूप से समय देना चाहिए। सरकार को समय मिलाना चाहिए और पिछले में भी धैर्य होना चाहिए। कल और आज सदन में सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के छताक्षेप के उपरांत एसआईटी का गठन हुआ। सब यह है कि मोटी सरकार ने अंततः किन्हीं भी परिस्थितियों में एसआईटी का गठन किया लेकिन पिछली सरकार ने तीन साल तक उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, छताक्षेप और दिशा निर्देशों के बावजूद एसआईटी के गठन में किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी।

जल्द तक अंतर्गत्वीय समूह में एकजुटता बनाने की बात है, छोटे सकता है पूर्व की सरकारों ने तमाम प्रायास किए हैं। लेकिन जल्द तक देश और दुनिया में कालेधन के मुद्दे पर अंतर्गत्वीय समूह में एकजुटता के संदेश भेजने की बात है, यह उपलब्धि सिर्फ मोटी सरकार के साथ में जाती है। इससे पहले यह संदेश देश और दुनिया के बीच कशी नहीं गया था। आज देश के बहुत बड़े समूह को मोटी सरकार से बहुत अपेक्षा है। मैं सरकार से सदन में अपील करती हूं कि कालाधन अग्र यात्रीय संपदा है तो इसे सार्ट्रीय संपदा घोषित करने के लिए यहि आवश्यकता पड़े तो विदेश क्षेत्र ताएं, कानून बनाएं वर्तोंकि यह यात्रा की संपत्ति है। यह देश के उन मेहनतकारी, गरीब, दलित, पिछड़े समूह के सर्वाधारा वर्ष के लोगों की संपत्ति है, जिन्हें मोटी जी से विशेष उम्मीद है। इस उम्मीद की बहुत बड़ी वजह है वर्तोंकि मोटी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सामान्य वाय बेताने वाले से देश के प्रायान्मती बनाने का सफर तय किया इसलिए यह भी उस पिछड़े, गरीब सर्वाधारा वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो यह उम्मीद लगाये बैठत है कि जब यह पैसा देश के अंदर वापस आएगा, तो उसे देश के विकास कारों में खर्च किया जाएगा। लेपाल के जनकपुर में बैठत एक साधारण-सा वाय वाला भी यह उम्मीद करता है कि यहि मोटी जी उसके जनकपुर में प्रवेश कर लेंगे, तो उनके जनकपुर का सुधार हो जाएगा, जो उनकी सरकार के लिए नहीं हो पाया है। माननीय मोटी जी से लोगों में उम्मीदों का

यह स्तर है। इसलिए आज मैं सदन से अपील करती हूं कि हमारी सरकार कालेधन को सार्ट्रीय सम्पदा घोषित करने के सम्बन्ध में प्रायास करे और उसे देश में वापस लाए और साथ ही कालेधन की उत्पत्ति को देश के अंदर रोकने के लिए कारबंद उपाय निकालें। हमारे देश का जो 90 प्रतिशत तबका शोषित, कमजोर, दलित-पीड़ित है, वे उस पैसे से देश के विकास की उम्मीद लगाये बैठे हैं और यह सरकार के प्रायास से छी संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

\*m12

**SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):** Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity for making my small observation on this very important topic.

We had a similar discussion in the past also. On December 14, 2011, there was a threadbare discussion on black money. There was a motion moved by Shri L.K. Advani on the same subject and the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee replied to that. In that reply, he had narrated the steps taken by the UPA Government in unearthing unaccounted money, curbing ill-motivated action of tax evading and tax avoiding. Now, the BJP is criticising that the UPA Government did nothing and they have done a lot of things. Shri Pranab Mukherjee in his reply had proudly announced on the floor of this House that the UPA Government was able to unearth Rs. 66,000 crore of unaccounted money. Similarly, the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh in G-20 Summit had declared and appealed to the world that:

"G-20 countries should take the lead in agreeing to automatic exchange of tax-related information with each other, irrespective of

artificial distinction such as present or past, tax evasion or tax fraud in the spirit of our London Summit that the era of bank secrecy is over."

Similarly, he was inviting the attention of the world to this very vital issue. A lot of things were done during that period and I do not want to go into details of those things.

The BJP leaders were saying that they have done a lot of things from their side. We can very well understand the dilemma of the BJP. They are having their own problem in swallowing the slogans they had raised during the last election. During the last election, on this subject, they made capital out of it. At that time, it was one-step forward and now, the BJP is following a two-step backward strategy in this regard. Shri Venkaiah Naidu is here now. He was explaining the calculation of 100 days according to them. It was a wonderful calculation. It was a new definition for 100 days. Maybe the BJP's 100 days may be equal to our 1,000 days.

Whatever it may be, Sir, we have to realise the fact that a huge amount of unaccounted money is there within India and also in the accounts of Indian individuals abroad. That is also a huge amount. The figure may be different. The BJP wants to claim that it is Rs. 25 lakh crore while Ramdev's projection Rs. 45,000 crore. According to the Swiss Banks Association, it varies between US \$ 1,500 billion and 1,900 billion. The BJP's Task Force's projection during the election was that it may range between US \$ 500 billion and 1,500 billion. Whatever it may be, it is a big evil. So, what is to be done? Whatever is to be done, it needs to be done vehemently. Instead of mud-slinging, we have to put our heads together and find out exactly what legal, economical and practical action can be taken to curb these bad tendencies.

It is very clear that all are talking about the evils of black money, but what exactly is the solution? We have to identify first who the real individuals are who have kept their money in foreign banks and then, find out the quantum of legal and illegal money. Thirdly, there has to be an assessment of criminality involved in it. India being a party to various international treaties, we must make a specific and clear-cut legal method to bring back black money from abroad.

We have to understand about some realities. These kinds of tendencies cannot be curbed / stopped one fine morning. A country cannot be free from all kind of evils one fine morning. Somebody was mentioning about the American experience. America always takes a double standard. Of course, America might have brought back black money, but at the same time they are providing havens for black money from other nation. They are having an island there, and they will not disclose the names of the depositors. That is their strategy.

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Madam, I am going to conclude. As mentioned by my former speakers, there is a huge amount of black money within India also, which we have to take into consideration. We have to consider very seriously about the Indian situation also when we are talking about foreign money and deposit. For example, people were saying about smuggling. I do not want to enter into that issue.

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Similarly, my friend was saying about election reforms.

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Yes, Madam. How does the black money come, and how is it utilized in a ruthless manner? All these things will have to be taken into consideration. What I am saying in brief is that the Government should take very vehement action irrespective of all other claims.

I once again appeal to the Government to be serious on this issue. The Government should come forward to take very vehement action on this evil instead of doing only lip-exercise.

With these few words, I conclude.

\*m13

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (गालंदा) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, विदेश में जमा काला धन वापस लाने की वर्ता में मुझे आग लेने का आपने अवश्य दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।

काले धन पर कल से सदन में वर्ता ढो रही हैं। पंद्रहवीं लोक सभा में भी ठम लोग थे और इस पर वर्ता कुई थी, तोकिन आज तक उसके बारे में लोग समझा नहीं पाए कि काला धन कैसे वापस आएगा। पहले जो साथी इधर थे, आज उधर ढो गए हैं और पहले जो उधर थे, आज इधर आ गए हैं, तोकिन आपा बदल गयी हैं। पहले इस साइड से जो जवाब आ रहा था, अब वह उस साइड से आ रहा है। खासकर प्रधान मंत्री गोटी जी ने चुनाव के समय पूरे देश में धूम-धूमकर जनता के बीच यह बात कही थी कि आप अगर छमें जनादेश देने तो निष्ठित रूप से मैं काले धन को वापस ताँग और इस देश के छर परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। विदेशी में इतना काला धन जमा है कि उसके वापस आने से देश खुशहाल होगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी मिट जाएगी और अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, देश की जनता यह पूछ रही है। ठम लोग भी बोतू में जाते हैं, लोग सवाल करते हैं कि जन धन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए हैं, वहा उसमें पैसा आएगा। ठम लोगों को ऐसे सवाल सुनने को मिलता है। माननीय प्रधान मंत्री जी नहीं हैं, तोकिन वरिष्ठ मंत्री यहां हैं। सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि कब तक यह पैसा आएगा और उन गरीबों के खाते में कब तक जाएगा? यहीं सवाल मैं यहां रखना चाहता हूँ और देश की जनता जवाब सुनना चाहती है। अगर प्रधान मंत्री जी यहां होते, उनका जवाब आता तो निष्ठित रूप से अच्छा होता।

\*m14

**अं. किरीट सोमेया (मुम्बई उत्तर पूर्व):** महोदया, काफी अच्छा लगता है। वास्तव में अच्छे दिन आ गए हैं, वर्षोंकि, पूरा सदन एक आवाज में, एक ही सुर में काला धन वापस लाने की बात कर रहा है। कोई काला छाता लेकर आता है, कोई काला कम्बल लेकर आता है और अलग-अलग सुर में बात एक ही करते हैं... (व्यवधान) तोकिन एक बात का मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज पूरा देश एक ही रवर में बोत रहा है। कभी माननीय राष्ट्रपति तथा पूर्व वित्त मंत्री माननीय प्रणव मुखर्जी, विद्यमान जी, आडवाणी जी, मुलायम सिंह जी, अरुण जेटली जी, राहगे जी, जितेन्द्र जी, सुरीप जी, सब एक ही भाषा में बात कर रहे हैं कि काला-धन वापस लाओ। इसमें माननीय मंत्रिका अर्जुन जी का वह वाच्य उद्भूत करना चाहता हूं कि ये कुछ मात्रा में माननीय निशिकांत जी ने भी कहा। दिवेट को शुरू करते हुए जो माननीय मंत्रिका अर्जुन जी ने कहा, जो संसद की रिपोर्ट में लिखा है, 'Since independence'. आप तो 1985 से आगे गये थे। Since independence till now, discussion on black-money has taken place in some form or the other. Since independence, सरकार किसकी थी? यह संसद की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। माननीय मंत्रिका अर्जुन जी का वह वाच्य सुनकर और निशिकांत जी ने जो अनेक उदाहरण दिये, उसके संदर्भ में मार्क-ट्वैन का एक किरणा याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था कि "सिनेट पीना छोड़ना बहुत संज्ञ काम है, मैंने अनेक बार छोड़ी है"। आप इसका मतलब समझ गये ना। काला-धन की बात कांग्रेस वाले करते हैं तब यह किरणा उन्हें याद दिलाना पड़ता है।

अर्थात् महोदया, आज मैं पॉलिटिकल कम थोड़ा आर्थिक इश्यूज को ज्यादा टच करना चाहूँगा। This is fact. All of us have accepted that black money is the issue. जब डम काला-धन की बात करते हैं तो मेरे इश्यू होता है, how is black money generated? Let us concentrate on that. How is black money parked? How it is invested? The third part must be an action to stop further generation and an action to recover whatever black money is available whether outside the country or inside the country. आज पूरा देश छोंगे देख रहा है, छोंगे सब मानते हैं कि काला-धन एक समस्या है तो why cannot we concentrate on this issue whether on this side or on that side? छोंगे किया या आपने किया, सेंगे तो देश की होगी। We must discuss how it is generated. एक होता है करण्य, दूसरा होता है फ्रिमिनेट, तीसरा होता है ड्रव्स कारण्य, चौथा होता है माफिया, पांचवा होता है डाईटेक रिज़िम। जहां पर डाईटेक रिज़िम होता है वहां पर लोग कर बचाने के लिए इस प्रकार से काला-धन जैनरेट करते हैं। तो होता है to run a parallel economy which is one major issue. मैंने पहले सेशन में इसका जिक्र किया था कि कुछ बोग्स विटफंड कंपनियां ड्रव गर्भी, आठ महीने से मात्रिक जेल में हैं तो किन एक भी छोटा निवेशक बाटर नहीं आता है तो पैसा है किसका? The last point is the fake money, fake currency. ये जो जैनरेशन वाली बात है, गोदी सरकार इसके ऊपर ध्यान केन्द्रित करना चाहती है। बताइये, कैसे कंपेन्टेट करना है? पहला, करण्य नहीं होते। काम के बदले अब दाम नहीं होते। एक बार छोंगे करण्य रोक दिया तो सब ठीक होगा। काला-धन जैनरेट केवल फेन्ड के कारण नहीं होता है काला-धन जो जैनरेट होता है वह लोकल-बॉडी से लेकर, विधान सभा से लेकर केन्ड्र तक है। पहले डम सब भितकर उसके ऊपर कांसेट्रेट करें। बीजेपी की आज पूरे देश में सौ प्रतिशत सरकार नहीं हैं, लोकसभा में जरूर 282 सांसद हैं, तो किन विधानसभाओं में अलग-अलग पार्टीयों की सरकार हैं।...(व्यवहार) I am not saying that politicians generate black money. I am talking about what Government can concentrate on.

ਮਾਹੌਦਾ, ਮੈਂ ਏਕ ਔਰ ਬਿੰਦੂ ਪਰ ਕਫ਼ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਥਨਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਪੌਲੀਟਿਸ਼ਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਪੋਨੇਟਸ ਔਰ ਅਨਿਆ ਤੌਰ ਅਪਨਾ ਕਾਮ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾ ਅਪਣੋਗ ਕਰਾਹਾ ਹੈ। Next point is criminal activities. Third point is drugs. ਕਈ ਲੁਗਨੇ ਚੋਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਜਿੰਡੀ ਕਾਰਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ? ਲੋਗਸ ਹਿਟ ਫੱਟ ਕਾਰਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਜ ਸੁਣੀਪ ਦਾ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਔਰ ਰਿਸੈਪਟ ਸੇ ਵਾਤ ਕਫ਼ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਈ ਸੁਝੇ ਸਮਝਨ ਫਿਕਾ ਥਾ ਕਿ why should a bogus chit fund company go out of the way and extend gestures to politicians? ਕਿਸੀਟ ਸੋਮੈਯਾ ਜੀ ਆਪਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਲੋ-ਪਾਂਚ ਕਾਰੋਡ ਰੁਪਏਂ ਕਾ ਕੁਛ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਕਵਾਤੀ, ਲੋ-ਪਾਂਚ ਕਾਰੋਡ ਰੁਪਏ ਕੀ ਵੀਚੀਟੀ, ਅਨਕ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਤੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕਾਰ ਟੈਂਗੇ। ਮੈਂ ਟੋਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਚਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਕ ਕਾਈ ਆਕਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠ੍ਹੂ ਕੀ ਦੀ ਕਾਰੋਡ ਰੁਪਏਂ ਮੈਂ ਖਾਰੀਦਤਾ ਹੈ ਤੋ I have to apply my mind. ਮੇਰਾ ਕਫ਼ਨਾ ਵਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਕਾਮ ਫਲ ਕਾਰੇ ਕਿ ਵਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਿਨਾ। We have done it. ਲੱਗ ਔਰ ਆਪ ਮਿਲਕਰ ਆਪ ਸੁਝੇ ਵਾਤਾਏ ਕਿ ਫਲ ਕਿਸਾਂ ਝੂਲ ਹੋਣਗੇ ਹੈਂ, ਕਿਸਾਂ ਸਹ ਕੁਝਾਂ ਹੈਂ? ਆਜ ਸੀਰੀਲ ਏਸਟੇਟ ਮੈਂ ਛਿਨੁਤਾਨ ਕਾ ਕਾਈ ਈ ਗੀਂਵ ਕਾਈ ਈ ਜ਼ਹਰ ਮੈਂ ਕਾਈ ਈ ਪ੍ਰਾਪਟੀ, ਕਾਈ ਈ ਜਾਨੀਨ ਯਾਹਾਂ ਬੈਣ ਛੁਆ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਲੈਕ ਮੈਂ ਪੈਸੇਟ ਕਰਾਹਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ? ਵਹ ਵਾਰਤਾਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਵਾਟਿ ਲੱਗ ਵਾਰਤਾਵਿਕਤਾ ਕੀ ਛਾਉਣੇ ਔਰ ਏਕ-ਦੂਜੇ ਸੇ ਤਡੇਂਗੇ ਤੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਤੇ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ 2001-2002 ਦੇ ਲਈ ਸੁਮਕਈ ਮੈਂ 60 ਪਰਾਈਟ ਵਾਇਟ ਔਰ 40 ਪਰਾਈਟ ਲੈਕ ਮੈਂ ਰਿਖਤ ਏਸਟੇਟ ਮੈਂ ਪੈਸੇਟ ਹੋਣੀ ਥੀ। ਵਾਰ 1997 ਦੇ 2005 ਤਕ ਵਹ ਸੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਾਇਟ ਪੈਸੇਟ ਹੋ ਗਈ ਥਾ। ਲੱਗ ਰਿਖਤ ਏਸਟੇਟ ਪਰ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਫ਼ਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਇਥਕੇ ਅਲਾਵਾ ਯਾਹਾਂ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਫੋਨ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਯਾਹਾਂ ਕੇ ਕਾਰਣ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਯਾਹਾਂ ਜੋ ਬੱਦੇ ਕਾਂਗੈਟ ਕਿਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਤਾਕਾ ਕਿਕਕੈਕ ਫੋਰਨ ਮੈਂ ਦਿਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। Generation of black money inside the country and abroad are one and the same thing. They are linked to each other. ਯਾਹਾਂ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਕ ਵਾਹਾਂ ਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਅਲੋਕ ਤਾਦਾਹਣ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੁੰਦਾ। What can we do in the case of tax havens? We can unanimously decide ਮੈਂ! ਟੈਕਸ ਫੇਵਨਸ ਕਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈ? ਯਾਹਾਂ ਤੀਵਰ ਪਰਾਈਟ ਕਾਂਪੋਨੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਯਾਹਾਂ ਤੀਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੱਗ ਸਥ ਮਿਲਕਰ ਨਿਰਧਾਰ ਕਾਰੇ ਕਿ ਤੁਮਹੈ ਫੇਂਸ ਮੈਂ ਤੀਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਤੋ ਯਾਹਾਂ ਵਾਤੀ ਕਾਰਪਨਿਆਂ ਥੀ ਸ਼ੇਤ ਕਾਰਪਨਿਆਂ ਖੋਲਤੀ ਹੈਂ। ਆਈਸੀਡੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾ ਕੀ ਤਹਾਨਾ ਥਾ। ਯਾਹੀ ਵਿਧਾ ਅਮੇਰਿਕਾ ਕੀ ਥੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਅਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰਫ ਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, developed countries are also facing the same problem. ਟੈਕਸ ਫੇਵਨ ਕੀ ਫੇਲਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਰਿਵਸ ਵੈਂਕ ਕਾਨਿਫਕੇਂਸ਼ਿਵਾਟੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਛਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੈਂਕੀਅ ਪਟਟਿਆ ਔਰ ਲੋਕਸ਼ਾਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਲਾਵਾਡ ਕਰਨੀ ਤੋ ਛੇਣੀ ਤੋ ਜਨਕ ਲਿਏ ਅਪਣੇ ਫੇਂਸ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਹੋਣਾ। What is required is nothing but intention, determination and action. ਮੌਤੀ ਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਤੀਨੋਂ ਵੀਂ ਪਾਂਚ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅਨਦਰ ਦਿਖਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਨਟੈਨਸ਼ਨ ਥੀ ਸਿਲਾਹਰ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਥੀ ਹੈ ਔਰ ਏਵਨਨ ਥੀ ਹੈ। ਸੌ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੁਗਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਾਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਿਤਾ ਹੈ। ਅਥ ਕਿਸਕਾ ਥੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਣਾ, ਵਹ ਛਿਨੁਤਾਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਏਣਾ ਔਰ ਇਨਟੁਸ਼ਨ ਨੇਰੋਂ ਮੌਤੀ ਜੀ ਕੇ ਕੋਟੀਵੂ ਮੈਂ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਖ ਕਾ ਏਕ ਨੰਬਰ ਕਾ ਫੇਂਸ ਕੇਨਾ।

\*m15

श्री असादुल्लाह ओवैसी (हैंटरबाला) : माननीय अध्यक्षा जी, आपका बहुत बहुत शुभिरूपा शायरे मशरूम ने मरकजी छुम्रात के बारे में एक शेर कठा था :

तुम्हारे बादे अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगे,

जो शाक-ए-गाजुक पे आशियाना बनेगा, वो नापायेदार होगा।

वर्षीय-ए-आज्ञा ने यह कहा था कि द्वं न खाएंगे, जो खाने देंगे। मैं छुप्पमत से आपके माध्यम से इस बात को कठाना चाहूँगा कि यह ऐसा कानून बनाएंगे या मौजूदा जो प्रीवेंशन ऑफ मनी टांडरिंग कानून है, उसको तरमीम करके इस बात को उस कानून में शामिल करेंगे कि अगर किसी छिन्दुरतान के फॉरेंग मुल्क में एकाउंट्स होंगे तो वह उसको अपने इंकम टैक्स में दिखाएंगे और कंपनीज का नाम दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाते हैं तो उसको प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम करार देंगे तथा उनकी प्रोपर्टीज को जब्त किया जाएगा। यह आप इस तरह का एक कानून बनाएंगे?

दूसरी बात यह है कि ड्मारे मुल्क में समायेदार जो हैं, ड्मारे सियारी निजाम पर कब्जा कर कुके हैं वे डमको यरगमात बना तुके हैं और खास तौर से दो बड़ी कौमी जमातों को, यहां जो बहस तुक्क, शायद ही कुछ तोगों जे इस बात पर मुतालवा किया होगा कि पार्टिसिपेटरी गोट्स पर मैं कछ रहा हूं कि उस पर आप बैन लगाइए। सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क की सातीनियत को इन पार्टिसिपेटरी गोट्स से है और मॉरीशियरा से पैसा याहां पर आता है, कोई यह नहीं पूछता कि वह किसका पैसा है? उसका नाम वया है और यहां पर आकर पार्क कर दिया जाता है। आज डम जानते हैं कि इसका मैं बगदादी बैन लगा है जिसने 80 मिलियन डॉलर का पैसा कमाया है। अब वह मॉरीशियरा में कंपनी बनाएगा और पैसा रस्तोंक एवं सर्वेंज में डालेगा तो ड्मारे रस्तोंक एवं सर्वेंज को भी तबाह कर सकते हैं। मुल्क में ठहशतगर्दी का भी पैसा आएगा तो पिर वया आप पर जिम्मेदारी नहीं आती कि आप मुल्क की सातीनियत को और मुल्क जिसे इन ठहशतगर्दों से खतरा है, उनको बचाने के लिए मुतालवा करता हूं कि पार्टिसिपेटरी गोट्स पर बैन लगाइए और जो कंपनीज और ट्रस्ट इंवेस्ट करते हैं, उनका नाम मात्रम करवाइए।

तीसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि एवाएसबीसी से जो नाम आए हैं, वे फ़ार्म्स के एक फ़ॉर्म्सीसी नेशनल ने ढंगे लिये हैं, यांत्रं पर मरकज़ी ट्रूकूमत यह कहती है कि डबल टैपरेशन एंड इंडेंस एंजीनेट हैं। छांगा एंजीनेट फ़ार्म्स से हो सकता है मगर वहां से आये एकाउंट रिपोर्ट्स के हैं। रिपोर्ट्स की ट्रूकूमत ने या बैंक ने डमको नहीं दिया। इसलिए आपको इनके साथ करने से कौन शेर करा है? टिरटैंटाइन बैंक जर्मनी से आता है। वह अतन इंडिपेंडेंट मुक्त है। टिरटैंटाइन बैंक के नाम हम अवाम के सामने ता सकते हैं। ट्रूकूमत कतरा रही है। 4 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का छाता दिया जा रहा है। मैं वित मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि अक्टूबर 2014 में आप सुप्रीम कोर्ट में वर्षों ज्ये कि 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको तरमीम किया जाए। वर्षा सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नं. 56, 71 और 72 में नहीं कहा था कि ये तमाम तीजे गतल हैं और आप नाम दे सकते हैं।

अमी हमारे मुम्बई से जो सांसद हैं, वही अच्छी बात कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि सिंगापुर में बॉयॉर्डिव्स नामक कंपनी ने सिर्फ 45 लाख का एकांत खोला। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकरी कॉलेटरल के 6500 करोड़ रुपये का तोन दिया और 2011 में 6500 करोड़ रुपये यांत्र पर हिन्दुस्तान में आए। वे फैसे किस कंपनी में ज्यों जो केजीडी-6 में डमारी गैस तातार कर रही हैं। वहां से सिंगापुर ने काई कमीशन को 2011 में लैटर दिया कि मालूम करिए कि इतना बड़ा पैसा आ रहा है। वहां यह हुक्मत जो वादा करती है कि हम न स्थाएंगे और न खाले देंगे। गोदावरी में केजीडी-6 में जिन्होंने पैसा खाला, वह पैसा मुल्क का है, वहां यहां क्षिताफ आप एक्षेन्ट लेने? अब मैं गाड़ी के लिए लोन एलाई करता हूँ तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लोन नहीं देता। तोकिन उस कंपनी को लोन दे दिया गया और उसके पास न कोई ऑफिस है, न कोई कॉलेटरल, न कोई ईविवेटेज थी तोकिन पिर भी 6500 करोड़ रुपये का तोन दे दिया गया।

आज हमारे पृथग मंत्री जी और एक बहुत बड़ी जमात के लोग एक बहुत सरमायेदार के एयरक्राफ्ट में फिरते हैं। वहां यह बात गलत नहीं है कि एसआईटी ने कहा है कि इस सरमायेदार की जो पॉर्ट कंपनी के ईविवेटेज थे, इसने गतत औरपाइसिंग करके 9000 करोड़ रुपये का टैक्स दियाया जबकि सिर्फ 3000 करोड़ रुपये के टैक्स थे। 5500 करोड़ रुपये कहां ज्यों? वहां यहां हमारे पृथग मंत्री जी उस एयरक्राफ्ट में बैठना बंद कर देंगे? अब आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ ... (व्यवधान) निशिकांत दुर्वे जी, मैं अदब से कह रहा हूँ कि मैं फ्रक्टर आदमी हूँ। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं ये दो अदम गिरालें आपके सामने दे रहा हूँ - केजीडी-6 और पावर कंपनी की, ये आपके लिए तैरते जा रहे हैं। अवश्य मुताब्ला यूनाइटेड नेशंस का जो कंवैन्शन है - आर्टिकल 14, 23, 40, 46, 52 वहां आप इन्हें शामिल करेंगे। यह आप मुल्क को गतत बावर करा रहे हैं।

\*m16

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Madam, thank you for giving me this opportunity to take part in this discussion. I may be given a little more time because two minutes is too little a time to put forth my views.

Madam, this is the right time for discussing the issue of bringing back black money from abroad. This is not because of BJP's coming back to power or NDA assuming power at the Centre but because the hon. Supreme Court has taken stock of the entire situation and vigorously monitoring the case of black money which has been stashed abroad. So, we are having little hope on the hon. Supreme Court and I hope this discussion will have its own impact in having further consequential actions.

It is an undisputed fact on the part of both the Opposition benches and also the Treasury benches that everybody is admitting the fact that black money is a menace to Indian economy and it is also being admitted that it is a parallel economic system which is being run in our country and is destroying the Indian democratic system. We are talking a lot about the black money. But in action nothing is taking place. That is the main thing which has to be considered. The very interesting fact to be noted is that the US based Global Financial Integrity Statement estimates that India ranks fifth in the world in illicit outflow of capital and at the same time it is one of the poorest country and ranks in the first ten poor countries of the world in terms of per capita GDP. On the one hand, we are having the fifth position in terms of the outflow of capital from India, on the other hand, India ranks amongst the first ten poorest countries of the world in terms of the per capital GDP. What a contradiction this is?

Madam, my first submission is that the entire Opposition as well as the Treasury benches have to join together to fight out the menace of black money. I would like to make two points. Firstly, Shri Kirit Sowmaiya has just stated that three issues have to be addressed. The first one is, how to bring back this black money? This is an assurance given by the hon. Prime Minister. In his election campaign it was very specifically mentioned that if he was voted to power, then definitely within 100 days the money stashed abroad will be brought back and each citizen will be getting Rs. 10 to 15 lakh. This was the assurance given by the hon. Prime Minister before the electorate. Now, the BJP is turning around and saying that it is an election campaign. If that be the case, then what about the other promises in the election manifesto? This is a Litmus Test as far as this NDA Government is concerned. It is because if one wants to test whether the rice has boiled or not, one need not take the entire rice from the pot, but only a sample has to be taken to find out if the rice has fully boiled or not. If that be the case, then the manifesto as well as the promises made and so many slogans made and also after assuming powers, all those promises made, they have to admit are hollow and are not going to be fulfilled.

The other point on which I would like to seek an answer from the Government is that, the hon. Minister of Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu ji was talking about the observation made by the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee in this House itself.

Madam, I would like to know the response of the present Finance Minister, Shri Arun Jaitley at that time. What were the observations made? My simple question is, whether Shri Arun Jaitley, the legal luminary in this country, Shri Prakash Javadekar, Shri Ravi Shankar Prasad, the esteemed leader, Shri L.K. Advani were not aware of the Tax Avoidance Agreement, the international treaties which were not applicable to them. Then why was this observation made at the time of the UPA Government? Why have they made this observation? The answer is, at that time, we were in the Opposition. Is it a genuine and justifiable answer? That means, at the time of election campaign, they have made so many promises and the promises cannot be fulfilled. What is the reason for it? It is because many procedural formalities are required to be fulfilled. Double Taxation Avoidance Agreement is there. All these were the reasons which were enunciated at the time of the UPA Government in justification for the difficulties which had to be faced. If that be the case, as the leader of the largest party, as the Congress Party yesterday had cited, the BJP and the Prime Minister owes an apology to the country first because he has made a promise which he is not able to fulfill due to procedural hurdles. He has to apologize to the Congress Party also because he has unnecessarily criticized the Congress Party at that time. If you want to enjoy the credibility of this Government, definitely, admit the fact and take stringent action.

Madam, what about the black money? Will the Government be able to bring back the black money or not? Is the money there or not? Is the illicit

outflow of capital there in the Swiss Bank as well as in other Banks? How many years have lapsed? Definitely, the money has already been siphoned out and it has gone to different routes. By different routes, it has come back to India by way of foreign institutional investment. By FDI, it has come to India.

If you go through the statistics, during the neo-liberal reforms in 1991, the illicit outflow was 9.1 per cent. Now it is 16.1 per cent because of the deregulation of the economy and deregulation will aggressively promote black money also. All these points have to be taken into consideration and stringent action has to be taken to bring back the black money.

With these words, I conclude.

\*m17

**SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR):** Hon. Speaker, regarding the discussion on black money, I was hearing all the speeches for the last two days and I have only two minutes to speak.

I feel it a joke when these bourgeois parties – the BJP and the Congress – quarrel with each other on black money. The Congress Party says that the Prime Minister, Shri Modi was campaigning in the elections that he will bring back black money. The BJP says that the Congress was ruling for the last 50 years in India and who is responsible for black money and who will bring back black money? They are quarrelling together. ....\* The cats will quarrel with each other. Children will cry and people will think â€\*. That is the relationship between the bourgeois parties. I feel this as a Communist when I am hearing the speeches.

The people of India have every right to know the names of all those accounts in foreign banks. After disclosure, full investigation is necessary to know how wealth was stashed away and for what purposes it is used. Apart from the holders of foreign accounts, their benefactors including the political parties and other entities should be hauled up. Black money should be confiscated and used for the alleviation of poverty in the country.

At the moment, Modi Government has given a list of just 627 persons which was given by the Government of France. There are other lists in the possession of the Government received from other countries and foreign banks. I hope that the Supreme Court will get all this information and not confine it to Special Investigation Team.

## **18.00 hrs**

They must be made public. The Press reported one of the three names -- which was disclosed on 28<sup>th</sup> October by the Government – that person is a big donor to the BJP and the Congress. It only exposes the political connections of such people. Earlier the BJP Government was repeating the argument of its predecessor, that is the Government led by the UPA II, that it cannot disclose the names of the black money holders as it will breach international agreements. After the Supreme Court punctured this argument, it is now crying about rights of privacy of individuals and companies. This is nothing but a crude attempt to shield the culprits who have stashed away our wealth and money and deposited it in foreign banks for ulterior motives.

It is believed that the quantum of black money in India is worth three trillion dollars that is equal to the country's GDP. There is no question of rights to privacy of individuals and companies about our internal issues. Our Government can take action against the black money holders in India. What action is the Government going to take against the black money holders in India, not in foreign countries? It is necessary that pressure must be built to force the Government to publish all available information on stashing away of money by Indians. ....(Interruptions) It is stated that the total amount involved is more than three trillion dollars, that is equal to the country's GDP. It is the public money that has been stashed away. ....(Interruptions) Hence, merely identifying the culprits is not enough. Measures need to be initiated to confiscate the entire amount. ....(Interruptions)

**HON. SPEAKER:** It is six o'clock. अभी छारे पास तीन-चार लोग बोलने वाले हैं और मंत्री जी भी अभी रिप्लाई ठेंगे। ये तीन वक्ता और रिप्लाई ठेंगे तक आप सबकी अनुमति से छम सदन का समय बढ़ाते हैं।

**अनेक माननीय सदस्य :** महोदया, ठीक है।

**श्री मनिलकार्णन खड़गे (गुलबग़ा) :** महोदया, बहुत से मेंबर वर्लेशिप्सेशन पूछते हैं तो रिप्लाई में समय लगता है।

**माननीय अध्यक्ष :** ये तीन लोग दो-दो मिनट बोलने वाले हैं। उनकी बात दो जायेगी और पिर मंत्री जी का रिप्लाई दो जायेगा। आज रिप्लाई करा देते हैं और तब तक सदन का समय बढ़ा देते हैं। ये तीन लोग थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे और पिर मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। तब तक सदन की कार्यवाही बढ़ायी जाती है। धन्यवाद।

Shri Jayadevan, please conclude your speech.

**SHRI C.N. JAYADEVAN :** At the moment, the Government's approach seems to be just to force the compliance of the tax laws. If the guilty persons pay the taxes and penalty, they will be let off. This is nothing but shielding the criminals and it should not be allowed.

The Union Government has revealed to Supreme Court names in three cases. Among them is a mine baron of Goa. It is simultaneously revealed that this company has contributed huge amounts to the coffers of both the Congress and the BJP. Latter one is the bigger beneficiary. This company is charged with low invoicing of its exports and illegally mining iron ore. All has been done under the patronage of the ruling politicians. That is what I want to say. The ruling politicians quarrel amongst one another. You are asking the people as to who is responsible. The party which has ruled up to this time and the party which is now in power are responsible for this. That is all.

**HON. SPEAKER:** Thank you. Already we have discussed it for more than four and half hours. So, today we will complete it.

Shri K.C. Venugopal.

\*m18

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, at the very outset, I would like to say that the BJP had created an atmosphere by large-scale political campaigns only for winning the election, not for serious action. The misleading campaign was led by the present hon. Prime Minister himself saying: "We promise the people that black money will be brought back and distributed to the people." The people believed it and they voted for the BJP. They came to power. What did the people get? What are they giving to the people? There is no new initiative except the SIT formation under the insistence of the hon. Supreme Court. They are telling that the SIT is their baby but the SIT is actually the baby of the Supreme Court, not theirs.

The hon. Finance Minister said this in the Rajya Sabha yesterday. We read it in the newspapers today. Yesterday, while replying in the Rajya Sabha, the hon. Finance Minister was explaining to the people about the long procedures and technicalities in bringing back black money and the Double Taxation Avoidance Agreement which prevents him from disclosing the names of black money holders. After the hon. Finance Minister's reply in the other House, you are very clear that you are not serious about bringing back black money.

Yesterday Shri Anurag Thakur in his speech said that already the Congress has demanded revealing the names of black money holders. Why? The Congress has the interest to protect the black money holders. But here we have the list.

On 18<sup>th</sup> January, 2014 Shri Ravi Shankar Prasad said putting forth the Government's argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public due to the Double Taxation Avoidance Agreement. It is quite baseless. Shri Nitin Gadkari also said it. Shri Prakash Javadekar also told that. I would like to put a question to Shri Anurag Thakur. While asking the Congress party for revealing the names of the black money holders, did they not know about the Double Taxation Avoidance Agreement? They should tell the people. They are now telling that the Double Taxation Avoidance Agreement is preventing them from revealing the names.

Yesterday, Shri Mahtab told - He is not present now - that the Congress has some fear of taking action. We have no fear. We are not in power now. They are in power. They have freedom. We know what the BJP is doing. Without any majority, you installed a Government in Maharashtra. You are changing the name of Rajiv Gandhi in the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana and the name of the Airport of Hyderabad. You are doing a lot of things. Your attitude against Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi is seen by the people for the last two or three weeks. It is such an attitude displayed by the BJP towards democracy and towards the Indian National Congress. Therefore, you have the freedom. We do not want your mercy. At least, you reveal the names. Who is stopping you from revealing the names? That is what the country needs to know. Therefore, the hon. Finance Minister has a duty to tell the people why this baseless promise has been made to the people that within 100 days they would bring back black money and it would be distributed to the people? Actually it is a cheating towards the people. That is what my statement is.

Then you are asking about what our Government has done. That is a question put by them. Shri Nishikant Dubey told about the then Finance Minister Shri Pranab Mukherjee's White Paper on Black Money. That White Paper reveals that. In the White paper laid before the House in 2012, it is said:

" â€¦Joining global crusade against black money" - "India's actions through the G-20..  
India has been a strong proponent of transparency and exchange of information for tax purposes and has pushed the G-20 forum to exert pressure on countries that do not conform to the international standards of transparency."

At the London Summit of April, 2009, India played a major role in developing international consensus for taking action against tax havens. It was an Indian initiative of November 2010 at the Seoul Summit and the G-20 gave a call for concluding tax information exchange agreements. Prior to this, some countries were not willing to enter into Tax Information Exchange Agreement. Therefore, these things were done by the UPA Government only. You are doing an extension of things which the UPA Government had done. What new initiatives you have taken? That is what we would like to know.

Hon. Supreme Court has made a statement. Why are you holding protective umbrella for these people? Is this a silly question? Hon. Supreme Court asked the Government as to why you are holding protective umbrella. The Supreme Court had observed that they have no belief in you. Actually, it is non-confident statement against the present Government. Now, you are not serious about the Supreme Court's verdict. But when you were in the Opposition, when the UPA regime was there, when the Supreme Court's observation was against the UPA, you celebrated. You celebrated for election propaganda. Now, you are keeping mum on the Supreme Court's observation. Shri Arun Jaitley, hon. Finance Minister is not here. When 2G incident happened, I was sitting in the Treasury Benches. Before the report of the CAG was presented in Parliament, the Report was leaked to the Press. By using that press statement, you moved an Adjournment Motion in the House. The CAG called Press Conference against the then Government. At that time, you celebrated. Now, hon. Finance Minister is telling the CAG, don't sensationalise the issues. It is actually double standardsâ€¦...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Yes, please conclude now. Actually, you don't have time. I have given only two minutes. Please conclude. This is not correct.

...(Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I am concluding. This is the double standard of the present NDA and the BJP Government. Therefore, the country needs a strong apology from this Government for giving false promise to the people. Otherwise, definitely it would boomerang on you. With these words, I conclude.

\*m19

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you very much, Madam, for giving me an opportunity to speak on this subject. I, on behalf of my Party, YSR Congress Party, would like to express my views.

I would like to express my Party's views and also my views on black money. Press says that Rs.80 lakh crore are deposited in the banks. Even if we take the minimum as Rs.30 lakh crore, that is equal to 1.5 times or more of this year's Budget. What a great amount, Madam! If we can bring back all these amounts, all the social welfare schemes and developmental schemes can be implemented in this country. Poor man's life would be definitely brightened. *Swacch Bharat* which requires Rs.2 lakh crore to provide toilets to 13 crore families; education to all, health to all; linking of rivers, etc. can be implemented. But unfortunately, still we are not able to do it.

I would like to say with all sincerity that the countrymen have great faith in the present Prime Minister, hon. Narendra Modi ji. With the leadership of Shri Narendra Modi, as well as Finance Minister, people believe that the Government would bring back this black money and develop the country. With that faith only, the countrymen voted BJP to power. Excluding the alliance partners, BJP was given the absolute power. Please act on that. With your power, determination, expertise, mechanism and the whole Government machinery at your command, please act and bring back black money so that the country can be developed well. If you fail, the countrymen will be very much disappointed with you. Please use all your powers and bring back this money and develop the country for which the people of this country have given power to you.

\*m20

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोरह्या, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल से इस विषय पर गंभीर वर्चा हो रही है। मैं इस पर कोई आंकड़ा पेश नहीं करने जा रहा हूं वर्योंकि आपने इस पर मुझे मात्र तो मिनट का समय दिया है।

मुझे एक बात समझा मैं नहीं आ रही है कि इस विषय पर जिस गंभीरता के साथ वर्चा होनी चाहिए थी, उस में सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप वल रहा है। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को गंभीरता से लिया और जनता ने इस पर विचास किया है। इससे पहले भी उधर बैठे हुए लोगों ने इस सवाल पर गंभीर वर्चा की, देश के लोगों को यह अहसास कराने की वर्चा की कि हम रकैम को रोकेंगे, हम काले धन को वापस लाएंगे, हम इसके बारे में कानून बनाएंगे, तेजिन जनता ने इन पर विचास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। इन्होंने उन्हें डायलोग में रखा और फिर ये लोगों को डायलोग में डालना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक व्यक्ति को इसके लिए प्रायस करना होगा। नेहरू गोदी जी की सरकार और माननीय प्रधान मंत्री ने लोगों में एक विचास पैदा किया है। एक राजनीतिक संकट, जो विचास का संकट पैदा हुआ था, उस संकट को इस सरकार ने दूर किया है। इसलिए आज इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यह काला धन कहीं रखा हुआ है कि उसे कोई उठा कर ले आए। यह एक नीतित का सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नुड अवैरोस देकर फिन-फिन स्टरें पर इन चीजों को रोका जा सकता है और पलिक मनी को हम कैसे बेरट यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका प्रयास यह सरकार कर रही है। अभी इसमें जनता का विचास है। उधर के लोग आज भी उसी डायलोग में पड़े हुए हैं।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाया था।...(व्यवधान)

श्री मुत्तायम सिंह यादव : मैंडग, छ: बजे के बाद तो लंब पैकेट दिया जाता है। हम तो युवाओं से शूरू हो जाते हैं। हमें लंब पैकेट दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : अभी इतना समय नहीं हुआ है।

डॉ. अरुण कुमार : मैं कहना चाहता हूं कि यह काला धन एक दिन में पैदा जाए हुआ है। चाया घोटाला हुआ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोतों हुए दो मिनट हो गए।

डॉ. अरुण कुमार : महोरह्या, एक मिनट और टीजिए।

महोरह्या, बिहार में चाया घोटाला हुआ। चाया घोटाले के बाद जो वहां सरकार बनी, उस सरकार में भी घोटाला हुआ। अभी कौशलेन्द्र जी बोल रहे थे कि वहां मर्दों की बत्तेदानी निकाल ली गयी।...(व्यवधान) बिहार में इतनी बड़ी तूट हुई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वहा बोल रहे हैं?

डॉ. अरुण कुमार : मैंडग, यह सारा रिकॉर्ड है।...(व्यवधान) बिहार में इस पर आरी रकैम हुआ है। अभी दवा घोटाला हुआ।...(व्यवधान) सारथा विट फंड के लोग हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अरुण कुमार जी, आप कंवलूड कीजिए।

â€œ!(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पर्तीज अरुण कुमार जी, अब समाप्त कीजिए।

â€œ!(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार : माननीय सदस्य, आप थोड़ा धैर्य रखिए।...(व्यवधान) एक मिनट सुनिए। आपकी संख्या इतनी है कि आपने यहां ड्रेस कोड के साथ अपना कोड मिला लिया है।

माननीय अध्यक्ष : अरुण कुमार जी, अब आपके पास कुछ प्रायंत नहीं है। अब आप समाप्त करें।

â€œ!(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार : मैंडग, मेरे पास बहुत प्रायंत हैं। इसे जरा कंवलूड तो करने टीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, जल्दी कंवलूड करिए।

â€œ!(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार : मैं यह कठ रहा हूं कि यदि ये आवरण इनका पहले रहता तो इतनी संख्या में नहीं आते। शारथा विट फंड पहले खुला रहता तो इतनी संख्या में भी ये नहीं आते। इस तरीके से जो

आवरण हो रहा है, निश्चित तौर से आज देश में भूताचार एक मुद्दा है। एन.डी.ए. की सरकार ने मजबूती से जनता में विद्यास पैदा किया है। ये इस तरह का आवरण कर रहे हैं, एवशन कर रहे हैं।  
हमें पूरा विद्यास है कि पूरी जनता इसमें भरोसा करते हुए इस एवशन को देख रही है और आपके एवशन को भी देख रही है, इसलिए इसमें सहयोग कीजिए, तभी भला है। निश्चित तौर से कालाधन आएगा और कालाबाजारियों पर रोक लगेगी।

\*m21

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, thank you very much. I will take just two-three minutes. Since Jaitley ji has not yet come, we have some time. (Interruptions)

Madam, we have had a long discussion on the issue of black money stashed abroad and Members have given very serious suggestions. The main complaint was that today's Prime Minister during election campaign had promised that he would bring back the black money. He had assured the Indian people that they would get Rs. 15 to 20 lakh per family. I shall not waste time of the House by asking the BJP to apologize for their false assurance to the people of the country. I leave it to their conscience to decide whether to do it or not. I have only three concrete suggestions. I will be very brief.

The black money estimate is not there. It is from 500 billion US dollars to 2 trillion US dollars. One billion is thousand million or hundred crores. So multiply it by sixty; we will know how much black money is there.

The biggest problem with black money is that the money goes out of India and it comes back through the Mauritius route by what is known as round tripping. I want to ask the Finance Minister whether he is prepared to ban global participatory notes through which people enter the share market to prevent the round tripping of black money.

Secondly, Madam, much of the black money comes to India during elections. It is alleged that the ruling BJP had spent – this is unconfirmed report – Rs. 25,000 crore in the Lok Sabha elections and subsequent Assembly elections. It may be correct; it may not be correct. ... (Interruptions) We could see, in his latest book mentioned that... (Interruptions)

HON. SPEAKER: That name will not go on record.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: किसी का भी नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Okay, I will not mention. Rs. 25,000 crore is the money you spent in the Lok Sabha elections.... (Interruptions) I will talk about Saradha. (Interruptions)

Now, my question simply is that whether the Government is prepared to bring forward electoral reforms so that there is a ceiling on the spending by political parties instead of just a ceiling on expenditure for individual candidates.

Lastly, the plea the Attorney General took before the Supreme Court and the Finance Minister took is that the present Double Taxation Avoidance Agreement has a clause which is called the confidentiality clause. I want the Finance Minister to declare in this House whether he is prepared to revisit the confidentiality clause and work out the Double Taxation Avoidance Agreement. It is not necessary for all the countries. We have 92 such agreements. Let us just tackle the tax havens. Just take away the confidentiality clauses from the Double Taxation Avoidance Agreement. I will end by saying this that the question is not 'whether' but the question is 'when'.

Yesterday, Anurag Thakurji has mentioned our Chief Minister's name. It was uncalled for. We did not mention the name of the former Karnataka Chief Minister, who was arrested by the CBI. We did not mention the name of the former BJP's President, who was arrested. We did not mention the name of BJP's present President.... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Saugata Royji, it is over. You do not have any point to raise.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.

... (Interruptions)

\*m22

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Madam Speaker. Yesterday and today I heard the speeches and my impression is that it is simply a blame game.

Madam, you have been there in the Parliament for so long. You know that in 2010-11, we also had a discussion about black money when the other party was in power. That party is in the opposition now and this party is in power. So governance and government do not change according to

political parties is what I believe.

But what I am worried about is that when our grand children or our great grand children 50 or 60 years hence sit back and peruse records of these two days of discussion, I am sure that somewhere we must also acknowledge the fact that there is a strong possibility that they will be amazed to know as to what were these people actually doing in the 16<sup>th</sup> Lok Sabha. Is this the level of discussion they had about something so serious, about a parallel economy, a staggering amount, and these people were talking just about Congress, BJP, Trinamool and BJD? This is where we are. This is what our level is. This is very much worrying for all of us. I am sure you would also be worried. I am not excluding myself from this thing. I am also very much part of this House and I am also worried.

Black money, as you know, has very many different connotations in different parts of the world. One of our colleagues earlier mentioned that in some countries the black money may not have the same connotations as it may have in other countries. Our tax laws are of a particular nature. Some other countries like Cayman Islands or Fiji – a lot of people are visiting Fiji nowadays – or Mauritius have different tax laws. Tax laws vary, countries vary, so what is legal or illegal also probably varies. Therefore, the time has come when we have to actually sincerely question our motives as to what we really intend to do.

There is one question that I would like to ask all the learned members including the hon. Minister. Hundreds and thousands of students go abroad to study every year. All the students barring none have to open a foreign bank account. Their parents might be depositing money in their accounts. Do we know or can we label all those students' accounts as being illegal money, black money or undeclared money? Who is going to differentiate as to which is the corrupt corporate's money, which is the student's money, which is the politician's money or which is the businessman's money? Who is going to do that? Do we have a mechanism for that?

Madam, before you ask me to finish I would like to actually break my own record because I am so humble. A couple of questions should go on record. Should all foreign bank accounts be investigated? How do we identify that money in a certain bank account is illegal or not? Students who go abroad have bank accounts too. Is the money in those bank accounts also unaccounted money? How are our estimations being made? Should we even be making estimations and promising or not promising?

Madam, the Prime Minister had gone to a place in my constituency, Talcher. He did promise that a sum of Rs.15 lakh would be given to each individual Indian. I have that on video. I am not hitting out at the Prime Minister. I respect him because the Prime Minister is not Mr. Narendra Damodardas Modi, he is the pride of India. He is my country's Prime Minister. I am speaking for my country. I am not speaking as a politician here on this floor. I am proud that he has at least given thought that this needs attention. That itself is a great beginning and I will give kudos for that. But, how do we go about it? Illegal money can be easily linked with terrorism and insurgency.

Madam, like one of the speakers did mention, whenever Indians sell or buy flats or apartments or land or something, a huge portion of that transacted money is in cash. That means, characteristically we are a corrupt nation. Everybody is involved in that. It hurts us but this is the truth. How do we stop that? So, illegal money can easily be linked with terrorism. Fifty years later, there would still be terrorism and there would still be insurgency.

Madam, there are many other questions. But all I would like to wind up with is this. There was a rock album which I used to listen to when I was young. The title of that is "How can Ted Nugent survive in a John Denver world?"

What it means, Madam, today is the world of Bitcoin. Bitcoin is a currency which is electronic in nature. It is a peer-to-peer dealing and there is no hard cash, no hard currency. People are now starting to deal through Bitcoins. It has started to happen in India. The Reserve Bank of India has warned the Government, and has also warned the people of this country: "Take care. You could be inviting trouble; you could be inviting legal action." Is the Government planning for the future or not? It is not yesterday that we have to look to. Yes, we have to get the black money back. We should make all efforts. But let us change our tax regime; let us change our tax laws; let us make tax paying an inviting factor so that I feel like paying tax, not that I want to run away from the Finance Minister, from all his IT sleuths and from all his people. Let me feel happy; let me feel proud to be an Indian that I pay tax. This is what I would like to say.

Let us think of the future. We have innumerable challenges coming up for this country, for the generations that are to come ahead, beyond us. Let us prepare this country today so that tomorrow they have a better existence.

\*m23

**वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) :** आदरणीय अध्यक्षा जी, दो दिन की इस बहस में सदन के बहुत-से माननीय सदस्यों ने अपने विवार रखे हैं। माननीय मलितकार्जुन खड़गे जी ने इस बहस की शुरुआत की थी। उनके बाद कई साथियों ने यहां कई सुझाव भी रखे हैं। मैं इस बात के लिए ध्यान चाहूँगा कि कल बहस दोनों सदनों में हो रही थी तो मैं कुछ समय इधर और कुछ समय दूसरे सदन में था। आज भी वहां बिल ठोके की जगह से, मैं अपनी वहां से लौटा हूँ लैफिन, जो भी विषय उठाए गए हैं, मैं उनके संबंध में कुछ न कुछ जानकारी निश्चित रूप से दी हूँ। दूर वर्ता ने जो काला है, उसके संबंध में मैं अपने-आपको सीमित नहीं रखूँगा। काते धन की समस्या देश के भीतर और देश के बाहर, दोनों स्थानों पर गंभीर है। अभी अंतिम वर्ता सत्पत्ती जी अपने विवार रखे थे, तो उन्होंने कहा कि देश का जो टैक्स कानून है, उसका प्रसारण इस प्रकार से कीजिए कि टैक्स देना सरल भी हो जाए, बहुत बोझ भी न तो, टैक्स देने वाला मुझे खुशी भी हो और अपनी योगिता आमदनी के अलावा कालाधन जैनरेट करने की कोई इच्छा भी न हो। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जब-जब किसी प्रकार का टैक्स, चाहे वह डायरेक्ट टैक्स हो या इनडिलीज़ुअल टैक्सेशन 70-80 प्रतिशत, कुछ मरातों में 90 प्रतिशत से ऊपर था, लैफिन छमारा टैक्स देस बहुत सीमित था और सीमित होते-होते छमारी विकास दर भी डें, दो, छार्ट प्रतिशत तक होती थी। दुनिया के देशों के अर्थशास्त्री छमारा मजाक और मस्तूत उड़ाते थे और छमारी विकास दर को कहा करते थे - This is the Hindu rate of growth. This came to be accepted as an economic terminology at that time. वह कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, डम डायरेक्ट और इनडिलीज़ुअल टैक्स को जब श्रीजेवत लैवल की तरफ ताए हैं तो छमारी टैक्स वारिकर भी बही है। इसलिए मैंने पहले कहा है और आज भी कहना चाहूँगा कि टैक्सेशन श्रीजेवत हो, जिससे सरकार का खर्च चल सके, टैक्स की बेस बढ़े, जिसमें टैक्स चोरी करने वाले को कोई इंसीटिव न हो। Those who have to pay taxes must pay taxes. We cannot allow either evasion or avoidance. Those who are not to pay taxes and who are not liable to pay taxes, against whom by merely raising demands we cannot generate more tax. Such taxes then get stuck up in courts. In the last few years as an economy we got a bad name from the world of investment that you are not a tax

friendly regime. So, what you have said I entirely accept. Our tax system has to be friendly to the tax payer both procedurally and otherwise, and that is exactly what, step by step, we are trying to do.

बहस के दौरान ब्लैक मनी कैसे यापिस आए और जो लोग यह अपराध करते हैं, उन्हें कैसे सजा मिले, जो विदेशी राते रखते हैं... (व्यवहान) जगदमिकवा पाल जी कह रहे हैं कि कम वर्ता दुई, तोकिन कुछ वर्ता दुई... (व्यवहान) इस प्रकार की वर्ता में एक राजनीतिक पक्ष भी रहता है। खड़े जी ने कल जब बहस आंखें की, मैंने उनका पूरा आपण सुना। स्वाभाविक रूप से उन्होंने राजनीतिक पक्ष रखना था, रखा। मुझे उसकी बिल्कुल शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है कि लोकसभा बुनाव छ: महीने पहले पूरा हुआ है और जनता ने जिन लोगों के आपणों को पूरे और सुनकर उनकी मरद नहीं की तो अपूरे आपण को पूरा करना कई बार सदन में भी एक अवसर मिल जाता है। So, the unfinished speech of a general election can be delivered in the House also. वह आपका अधिकार भी है और उस अधिकार का आपने बहुत खूबी से प्रयोग किया है। तोकिन मैं उससे प्रोक्त हो जांते और उसी बहस की दिशा में चला जांते, वह मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं केवल कुछ विषय, जो मैं मानता हूँ कि हर सदस्य की विंता के हैं कि ये सारा पैसा कैसे जनरेट होकर वहां जाता है और जो लोग रखते हैं, उनके खिलाफ वह कार्रवाई हो रही है? कानून या व्यवस्था में अब बाधाएं हैं तो वे कौन सी हैं और किस प्रकार से सरकार आपना काम कर रही हैं? आपने कहा कि आप आपना वायदा निभाइये। मैं इसे बिल्कुल राजनीतिक रूप नहीं दूँगा। इसलिए मूल विषय के संदर्भ में सदस्यों की जो विंता है, मैं केवल उसे संबोधित करूँगा। I will only address the meat of the matter. सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जो काला धन जमा है, उसे लेकर और कई बार मुझे भी, मेरे साथियों को और हो सकता है कि हम में से कई लोगों को रुपाल्टा नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के विषय का छम अध्ययन करने के बाद, ऐसी वर्ता के बाद एक दूसरे से भी सीखते हैं और दुनिया किस दिशा में जा रही है, उससे भी सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई, 2011 को, यानी साले तीन वर्ष पहले अपना निर्णय दिया। उन्होंने उस निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजोंकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता के तहत एक एसआईटी का गठन किया जाये। उसमें सरकारी अधिकारी भी होंगे। सरकार किस प्रकार से काम करेगी, यह उस एसआईटी की जिम्मेदारी है। उस निर्णय में उन्होंने कई बातें कहीं। एक विषय यह रखा, जिस पर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ और मैं माननीय सदस्यों से विनम्रता से विनती करूँगा कि इस विषय को केवल छम लोग एक ऐफेडेंशियल अध्ययन की टॉप से समझें, इसे राजनीतिक टॉप से मत लें। जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज या फैसले होते हैं, उनमें एक कांफिडेंशिएलिटी वर्लॉज होता है। उस कांफिडेंशिएलिटी वर्लॉज की आप उन्होंने कहीं और कहा कि आरतीय संविधान और कानून इसकी अनुमति नहीं देता कि आरतीय सरकार और उस संदर्भ में यू.पी.ए. सरकार के बारे में कठ रहे थे कि इन कांफिडेंशिएलिटी वर्लॉजेज वाली ट्रीटीज को स्वीकार करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने आपने फैसले में कहा। यू.पी.ए. सरकार को तगड़ा था कि ट्रीटी करना तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब कौन सी ट्रीटी करें, जिसके माध्यम से जानकारी मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें न्यायालिका कैसे कठ सकती है। जुलाई, 2011 से लेकर मई, 2014 तक, इन तीन वर्षों तक एसआईटी नहीं बन पायी। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विवाद किया जा रहा था कि ट्रीटी रूप में चलाता रहा। पहली मई, 2014 को जब बुनाव वल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में, सरकार की याचिका पर दूसरा निर्णय दिया और उन्होंने कठ दिया कि जो टिंब्रेस्टाइन एक टैक्स छैवन है, वहां 28 लोगों के खाते थे। इसकी जानकारी जर्नली ने आरत को दी। उसकी जो जानकारी आपको मिली है, वह याचिकाकर्ता को दे टीजिए। तब याचिकाकर्ता को सरकार ने जानकारी दी, जब यू.पी.ए. की सरकार भी तो याचिकाकर्ता के माध्यम से वह सार्वजनिक हो गयी। जर्नली ने तुरंत आरत को लिखा कि जिस आधार पर आपने छम लोगों सबूत दिये थे, आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आपने इसका उल्लंघन किया और अगे यह खाता पैदा हो सकता है कि अगर छम उल्लंघन करें तो दूसरा देश सहायता करता है या नहीं करता। इस समस्या के बारे में माननीय मुलायम जी ने यहां छोकर कहा था और मैंने आपासन भी दिया था कि मैं इसका उत्तर दूँगा। आप इसकी गंभीरता को इस टॉप से समझिए कि अपराध आरत में होता है, पैसा आरत का है, विदेश के खाते में जमा है, पैसा आरत को दे टीजिए, उसके खिलाफ असेसमेंट करने के लिए, उसके खिलाफ फौजादारी मुकदमा लाताने के लिए उस देश का सहयोग चाहिए। छम अपली पुलिस, आर्मी या अधिकारियों को तो वहां बेंज नहीं सकते हैं। कानूनी प्रिवेन्या के मुताबिक उस देश को छम करेंगे कि छम यह जानकारी दीजिए। आज से 20-22 जान घटते एक वर्ता था, जब खिलाता था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की आप में प्रिसिपिटा ऑफ ड्यूल प्रिमिगेनिटी कहते थे। इसका खिलात यह था कि जो पैसा वहां जमा है, वह किसी अपराध से पैदा हुआ है, If it is a profit of crime, छम में से निकला है, भ्रष्टाचार में से निकला है, आरस ऐक्ट में से निकला है, टैरिजम में से निकला है। अगर अपराध की यह कमाई है तो आरत दूसरे देश को कठे कि मुझे जानकारी दीजिए। दोनों देशों में यह अपराध अगर अपराध माना जाता है तो वे जानकारी देंगे। यह दूसरा दौर आया कि अगर वह पैसा टैक्स इकेजन का है और वोटी से रखा है तो देशों ने सहयोग करना आंखें कर दिया तोकिन सहयोग के लिए आपका उनके साथ फैसला हो, समझौता हो या उनके देश में कानून हो। टेवनोलॉजी वर्ली और अब सारी बैंकिंग और कम्प्युटिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में कंप्यूटर के माध्यम से सरलता से इंटरनेट पर पता चल जाता है, अब छम इससे तीसरे दौर में जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया को तीसरे दौर में सफलता मिलती है तो लोगों के लिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल, वहां का पैसा उड़कर वहां चला जाए, यह इतनी सरलता से संभव नहीं होगा। यह तीसरा दौर ऑटोमेटिक एवसरेंज आफ इफार्मेशन है, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, रियल टाइम में उनकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है। अगर कोई आरतीय अमेरिका में पांच मिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन करता है, एक देश से दूसरे में पहुँचता है तो अमेरिका उसी वर्ता भारत को इतिहास कर देगा। अगर वह ट्रांजेक्शन ईमानदारी के पैसे का है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तोकिन अगर वह पैसा अपराध या टैक्स इकेजन का है तो छम आप अधिकार होगा कि उसे सबूत मानकर उस पर कार्रवाई करें।

एक विडंबना है कि जितनी भी टैक्स ट्रीटीज़ भारत ने की हैं, जितने भी देशों के कानून बन रहे हैं, उनमें कालिफ़ोर्नियनिटी वर्लॉज़ हैं। इस वर्लॉज़ का सौभाग्य यह जी जिक्र कर रहे थे, इसका यूनिफ़ार्म पैटर्न बना है। देश जो अपना लोमेस्टिक कानून बना रहे हैं, जैसे अमेरिका ने एक कानून फटका बनाया है, उसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका में कमर्शियल ट्रांजेशन होगी, उसकी इतिला की जाएगी। इसमें कालिफ़ोर्निटी वर्लॉज़ होगी, ईमानदारी की ट्रांजेशन होगी तो वात सामग्रे नहीं आएगी, तोकिन अगर पैसा वोटी किया तुम्हा है या टैक्स देवेज़न का है तो उसकी जांव होगी, उस व्यक्ति के स्थिताप कार्डवाई होगी। उन्होंने छर देश को कहा है कि इन्टर गरनमेंटल एग्रीमेंट कीजिए। जी-20 विशेषज्ञ में छात की मीटिंग में यही तुम्हा इसके अतिरिक्त ओ.ई.सी.डी. में भी यह हो रहा है और इस दिशा में जब दुनिया वात रही है तो इन तमाम कानूनों में भी यह कांफिडेंशियलिटी वर्लॉज़ है। उसका अर्थ यह नहीं है कि यह जानकारी कभी भी बाहर नहीं आएगी। उसकी रिस्ट्रूवेशन है कि यह कब और कैसे बाहर आ सकती है। जब हमें जानकारी मिलती है, तो उसे लेकर हम सबूत इकट्ठा करें, लोधियों के स्थिताप कोर्ट में मुकदमा करें और जैसे ही मुकदमा किया जाएगा, वूँकि वह सुनी अदालत में होता है तो उसकी जानकारी सभी को वहाँ से सार्वजनिक की जा सकती है। तोकिन उससे पहले ये यहि आप जानकारी दे देते हैं तो पिर उस कानून का या उस ट्रीटी का उल्लंघन मानते हैं। अब तीन प्रकार के जो कैमेज़ छामेरे सामग्रे आए, उसमें वया हुआ, इसकी जानकारी मैं ठे दूँ ... (व्यापान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): You are repeating Shri Pranab Mukherjee's speech, and saying the same thing. ....(Interruptions) We want to know as to when the money is coming back....(Interruptions) Do you have any concrete plan or do you have any idea about it? ....(Interruptions) These are all repetitions of Shri Pranab Mukherjee's speech. ....(Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY : Sudipda, I am conscious of my lack of ability to explain anything to you. Therefore, if you do not have ... (*Interruptions*)

Madam, one of the reasons your Government failed was because they were not wanting to understand this. ...(*Interruptions*) Since you are going to be a future Leader of your Party, at least for future benefit try and understand this. ...(*Interruptions*) अब इसमें डम लोगों ने बता किया, यहि आप इसे पार्टीशन बनाना चाहते हैं, तो मैं पार्टीशन उत्तर भी दे रहा हूँ, जो मैं नहीं देना चाह रहा था। वहाँ तो तीन वर्षों तक एस.आई.टी. कैरेज न बने, यह दरखास्तारों वल रही थी। 26 मई को डमारी सरकार ने शपथ ली, 27 मई को कार्रवात समाप्ता और 29 मई की पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे एस.आई.टी. के समक्ष करने का पहला फैसला किया गया। ...(*व्यवहार*) The same instruction of the court applied to the UPA, but for three years you did not act. ...(*Interruptions*) 4 जुलाई, 2011 का फैसला आपके 26 मई, 2011 तक नहीं खीकार किया और एस.आई.टी. नहीं बनारी। ...(*व्यवहार*) आपकी नीति एस.आई.टी. बनाने की छी नहीं थी। ...(*व्यवहार*) उस फैसले के सम्बन्ध में एक विषय पर मेरे मन में भी पूँज है, तोकिन छग्ने पहले एस.आई.टी. बनारी। एस.आई.टी. बनाने के बाद जून के महीने में जितानी भी डिटेल्स ड्लारे पास तब तक आयी थी, अकाउंट होल्डर्स के नाम, उसके साथ-साथ उनके डिटेल्स, जो भी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध थी, सरकार बनाने के तीन साल के भीतर छग्ने उसे एस.आई.टी. के ड्लाले कर दिया। ...(*व्यवहार*)

Dada, I will explain all the names. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** कृपया आपस में बातें न करें।

અનુભૂતિ

PROF. SAUGATA ROY : Actually, we are interested in knowing as to when we are going to get the money back. ... (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : We want to know from the hon. Minister about the names. ...(*Interruptions*) When will the black money come back?

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you can continue.

...(Interruptions)

**18.56 hrs**

*At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay, Md. Saleem and some other hon. Members left the House.*

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: What are you reading Kharge Ji?

...(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, I want a clarification in this context. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : वर्तैरिफिकेशन रिपोर्ट पूरी होने के बाद होती है।

श्री महिलाकार्यवाल खड़गे : जेटली साधव, आप डिटेल्स के साथ बोल रहे हैं, खासकर प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजरल मैटर पहले से ही छाइट पेपर में आया है और उसके बाद भाषणों में भी आपने कहा है, लेकिन हमारा कहना है कि हम आपसे यह तत्वकों करते थे कि 100 दिन में जो 15 लाख रुपये छेक आदानी की जेव में डातने की बात थी, यह कहां गयी। हम यही आपसे पूछ रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि कांफिडेंशियलिटी वर्लॉज होने के बाद यह नहीं बता सकते। यह सब मातृमूल होते हुए भी आपने बाहर जनता को गुमराह किया। ... (व्यवधान) I am not telling about the Finance Minister. But your President, your Prime Minister and all people told about this. Except you, all people told about this thing. I have heard your speech and also debate. Except you, everybody told the same thing. Somebody told that within hundred days, we will bring back the black money. We will bring back and give Rs. 15 lakhs. ₹ SHRI ARUN JAITLEY: You worked hard to analyse all the speeches.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I have seen and observed. Naidu Ji is a senior man who has got experience, he told for Rs. 60 lakh. I want to know that at least that Rs. 60 lakh information is there or not. You are not telling. Therefore, we are not satisfied with your answer. We will walk out. ... (Interruptions)

**18.57 hrs**

*At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.*

...(Interruptions)

श्री एम. वैकेर्या नायडू : मैडम, खड़गे जी ने मेरा नाम दिया है, इसलिए मैं एक लाइन में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास निनिस्टर ऑफ पार्टीमेंटरी अफेयर्स के नामे दूसरा दायित्व है, इसलिए मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने दोपहर में उनसे उनके नेता के समक्ष पूछा था कि आपके सीधीआई डायरेक्टर के कहा कि 25 लाख रुपये करोड़ की राशि है। यह अधिकृत रूप में सीधीआई डायरेक्टर ने कहा। मैंने यह बात याद दिलाई, उसको यह भूल गए। मैं फिल कर रहा हूँ। आपकी मीटिंग में जब यह इच्छा आया था तो मैंने कहा था कि अगर बहस चाहिए तो हम बहस के लिए तैयार हैं। दो घण्टे की बहस मांगी, अब पांच घण्टे बहस करने के बाद भाषण देकर बाले गए। यह अन्याय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके साल की अनुभवी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने उनको आत्मेती सही मार्ग दिखाया है। अगर ऐसा व्यवहार ज्यादा करेंगे तो उनको गुकसान होगा। मैं इनका ही कहना चाहता हूँ।

**19.00 hrs**

श्री अरुण जेटली : हम लोग जब नौजवान थे और नए-नए विशिष्ट बने तो हम लोगों को एक सुझाव दिया जाता था कि जिस मुकदमे में तथ्य मजबूत हैं, तथ्यों की बात करो, जहां कानून मजबूत है, कानून की बात करो और जहां दोनों कमज़ोर हों, तो फिर मेरा पर शोड़ा सा दबाव डालते रहे। अब पूरी व्यवस्था को समझने के स्थान पर यही कहना कि सरकार ने वया-वया किया है, मैं इस बारे में आपको पूछ आंकड़े देंगा।

कई माननीय सदस्यों ने, वाढ़े खड़गे जी ने पूछा हो या मुत्याम सिंध जी ने पूछा हो कि यह स्थिति अब कहां खड़ी है, पैसा आएगा या नहीं आएगा, मुत्याम सिंध जी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तोनों ने पैसा निकाल दिया हो। मुत्याम सिंध जी, सत्याई यही है जो आपने कहा। मैं उसके भी तथ्य आपको देता हूँ। यह केवल राजनीतिक अंतर्विद्या का पिष्यां नहीं है।

तीन प्रकार की स्थितियों से निकलते हुए हम अब एटोमेटिक एवरसोर्ट ऑफ फंक्शन में जाते हैं। तीन तरह के स्थानों में जानकारी है, या सम्भव है। पहले स्थाने हैं 28 लोगों के जो निपटनवाटाइन नाम का एक टैक्स फैक्टर है, जहां लोग इस प्रकार का पैसा रखते हैं, उन स्थानों की जानकारी जर्मनी को मिली। जर्मनी के साथ भारत का समझौता था और जर्मनी ने उसके तहत जानकारी ढूँढ़ी थी। ढूँढ़े उसकी जांच करनी थी और सबूत इकट्ठे करने थे। उस सबूत में यह पता किया गया था कि कुछ लोग एनआरआई हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपको अधिकार है खाता रखने का, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई। ऐसे 18 लोग थे उनमें से जिनके नाजायज खाते थे। तो किन जब तक यह प्रक्रिया पूरी होती, तब यूपीए सरकार थी, वे लोग अपना पैसा बहां से निकालते रहे। हमने उन 18 के 18 के खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स कंवॉल्ड कर दी हैं। उस नाजायज पैसे की जो भी उन पर सजा या पैनल्टी लगा सकते थे टैक्स कौरें, वे सारे उन पर लगा दिए हैं। उसके बाद उन 18 के 18 पर फौजदारी का मुकदमा भारत के अंदर डाल दिया है।

इसके अतिरिक्त एवाएसलीसी का जिनेवा का जो बैंक था, यह पूरा मल्टी इंटरनेशनल बैंक है, उस बैंक का एक कर्मचारी दिलाल ब्लॉअर बन गया और उनका सॉफ्टवेयर वहां से उठाकर ले गया। उस सॉफ्टवेयर को ले जाने के बाद उसने यह सारा का सारा फ्रॉंट की सरकार को दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने यह बैच दिया। अब फ्रॉंट के साथ चूकि ड्गारा समझौता था, दुरिया के अन्य देशों के साथ भी था। फ्रॉंट ने दर देश के स्थानों की जानकारी उन देशों को दे दी। भारत को जानकारी मिली कि 2005 और 2007 के बीच में रिव्टजरलैंड के एवाएसलीसी के बैंक में इन 627 लोगों के ये एकांतर्दस थे। ये जानकारी 2007 के बाद 2008 और 2009 तथा 2010 में मिली होनी। ड्गारो रिव्टजरलैंड से समझौता था, उसमें यह प्रायत्यन थी नहीं था कि रिव्टजरलैंड द्वारा जानकारी दें। सन् 2011 में जाकर भारत सरकार ने रिव्टजरलैंड से यह समझौता किया। उन स्थाने वालों को 2007 से 2011 तक की मोहल्लत मिल नहीं। इसमें वे वया करते, स्थाने में दिनना पैसा छोड़ते। सन् 2011 के बाद जब यूपीए ने उनसे पूछा कि ढूँढ़े जानकारी दो, सबूत दो, तो उन्होंने कहा कि यह जो सारी जानकारी आपको मिली है, इसमें केवल नाम हैं, थोड़ी भी जानकारी है, सबूत नहीं हैं। हम आपको सबूत नहीं देंगे, व्यक्ति की यह चोरी के आधार पर मिलते हैं, रेतान डेटा है और रिव्टजरलैंड स्टोरन डेटा में आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। जब हमारी सरकार बनी तो स्थिति यहां तक पहुंची थी।

The Government of India is a continuing entity; I am therefore not referring to it on a partisan basis. हमने अपना एक प्रतिनिधि मंडल रिव्टजरलैंड भेजा और

उस प्रतिनिधि मंडल ने जाकर कहा कि आप हमसे समझौता और सहयोग कीजिए, उन्होंने कहा कि यह बोरी के डेटा पर हम समझौता नहीं करते। अवटूबर में हमने उनसे समझौता कर लिया कि पैसा ते भी गये, तेकिन ऐसे लोगों को ज्ञाता हो जाए, जिन्होंने इस देश का पैसा बोरी करके बढ़ा रखा, हमने इवेटजर्टेंड से चार मुद्राएं पर समझौता किया। उसका पहला अंश यह था कि आप केवल बोरी के दस्तावेजों के आधार पर हमारी मदद न करें, तेकिन अन्य हम कोई सबूत इकट्ठा करते हैं तो उन सबूतों के आधार पर तो आप हमारी मदद करेंगे या नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, हमने कहा कि फिर वहा टाइम-फ्रेम है जिसमें आप हमारी सहायता करेंगे। आप इन दस्तावेजों को कंफर्म या डिनाई करेंगे कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। चौथा, अधिक्य के लिए हमारे साथ बातचीत शुरू कीजिए कि कोई भी भारतीय अन्य रिवेटजर्टेंड में एकाउंट खोलता है या कोई ट्रांजेक्शन करता है तो there is an automatic transformation of information to us. Now, this four-point agreement has been put in force; this is an arrangement and we are in regular touch with them. इन 627 में कुछ के केवल नाम थे। अब व्यक्ति का नाम गिर जाए और पता न हो तो कहां छुड़ेंगे? हमने 427 नामों को शिक्षित कर लिया है और उन सब को नोटिस दे दिये हैं, उन सब की पैसी हो रही है। एक-एक करके कई लोगों पर फैजादारी के मुकदमें अदातातों में डाले गये हैं। जब मीडिया के मित्रों को जानकारी दिलेगी तो पता चलेगा कि उसमें बहुत प्रभावी तोग भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च तक उनकी टैक्स अरेसमेंट्स स्थान कर दें और जो-जो उसमें गैर-कानूनी माने जाएंगे, जिन्होंने अपाराध किया है, उनके खिलाफ फैजादारी मुकदमें दायर होंगे। दर साथ मुकदमें दायर हो रहे हैं। निचली अदातत में मुकदमें दायर होते हैं तो देश भर में जहां उनकी अरेसमेंट थी वहीं दायर होते हैं। उन 427 में से 250 लोगों ने आकर कबूल कर लिया कि यह हमारा एकाउंट था। यह सारी की सारी कार्रवाई एसाईटी के तहत हो रही है। अब सबाल यह है कि कुछ तोग तो पैसा निकाल कर ते गये, बढ़ियों का वरा होगा? दुनिया में वीसियों ऐसे केन्द्र और हैं जहां टैक्स फैन्स में लोग पैसा रखते हैं। आज हमने "डबल टैक्सेशन अवार्डेंस ट्रीटी" के तहत 92 देशों के साथ समझौते कर लिये हैं, तिरायें के साथ भी दृस्ताक्षर हो गये हैं तथा सात अन्य के साथ बातचीत चल रही है। टैक्स इंफोर्मेशन का जो फैसला किया है, 15 के साथ पहले से है, 2 के साथ और किया है तथा 29 और ऐसे देश हैं जहां पैसा रखा जाता है उनके साथ हम यह समझौता कर रहे हैं। ये तो केवल दो दैक्षिण्य टिक्कारीन और एवासालीसी रिवेटजर्टेंड के द्वारा, तेकिन जो लोग निकट भवित्य में पैसा रखते हैं, तो हम दुनिया के जितने ऐसे देश हैं, उन सब के साथ जो लाजर कम्पनियों औंफ लेन्स में, हम एटोमेटिक ट्रांसमिशन का समझौता कर रहे हैं। हम 48 बड़े देशों में अल्टी-एंट्रेस हैं, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। कोई भारतीय विटेश में और कोई विटेशी भारत में पैसा रखता है तो उसकी जानकारी शेयर करेंगे। जी-20 विसेजेन में माननीय प्रधान मंत्री जे इसी के लिए प्रूसास किया। औईसीडी में तुगा और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो अमरीका ने पटका नाम का कानून बनाया है, जो 2015 से लागू होगा है, वह अनिवार्य करता है कि हर देश हमारे साथ फैसला करेंगे कि एक दूसरे के ऐसे लोगों की जानकारी शेयर होगी। जो देश ऐसा नहीं करेगा, उसमें जो ऐमिटेंस जाएगा, केवल अमरीका से ही नहीं बिल्कुल उन देशों से भी जिन्होंने दस्ताक्षर किये हुए हैं। उस देश के उपर हम तीस परसेंट लगा देंगे, जिसको विलडोर्डिंग टैक्स कहते हैं। कोई एवसपोर्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें भी कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज है। वह कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज यह है और वह यह नहीं कहता है कि कभी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। तेकिन मान लीजिए ज्ञ में से किसी का नाम सामने आ जाता है और जांच में पता चलता है कि यह पैसा जारूर था। किसी एनआरआई ने रिजर्व बैंक की अनुमति से बाहर रखा हुआ था तो उस व्यक्ति को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। तेकिन नाजायज़ है और सुरक्षा है तो केस आतिए और नाम सार्वजनिक कर दीजिए। इसलिए विषय यह नहीं है कि जानकारी दी जाए या नहीं दी जाए, विषय यह है कि जानकारी कब दी जाए? The question is not whether to give information or not, but when and how to give information. कुछ लोग बहुत बहादुर बनते हैं और कहते हैं कि नाम तुरन्त दे दीजिए। ये जितने लोग बिना सुख्त और केस के नाम को सार्वजनिक करने का आग्रह करते हैं, तो उसको विलडोर्डिंग टैक्स के इस कानून पर दरताक्षर नहीं करेंगे। उसमें भी कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज है। वह कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज यह है और वह यह नहीं कहता है कि कभी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। तेकिन मान लीजिए ज्ञ में से किसी का नाम सामने आ जाता है और जांच में पता चलता है कि यह पैसा जारूर था। किसी एनआरआई ने रिजर्व बैंक के डम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्राप्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इन ट्रीटीज़ का सम्मान हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2011 के फैसले में कहा है कि यह कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज जलत है। दुनिया कहती है कि बिना कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज के डम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्राप्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इन ट्रीटीज़ का सम्मान हो।

अब विषय आया कि अधिक्य में या पुराने लोगों को पकड़ते हैं तो टैक्स किस माध्यम से करेंगे? मैं यह ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हमारे कानून में एक कमज़ोरी है और कमज़ोरी यह है कि जब पैसा पकड़ा जाएगा तो उसको वापस कैसे लाना है? उसको भी अब पूरा करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि एसआईटी भी इस विषय की खिंता कर रही है। इनकम टैक्स एवट में बाहर गाते का अधिकार नहीं है। गैंगे मनी टॉर्टिंग एवट का अद्यतन किया है, उसमें भी शायद कमज़ोरी है, तो भी बदलना पड़ेगा। अबर बाहर से नहीं लाए जाने के साक्षर हैं तो देश में उन्हें भी पैसे की उसकी जो सम्पत्ति है उसको कुछ करने का अधिकार होना चाहिए। इसे इनकम टैक्स में करें या मनी टॉर्टिंग में करें। यूनन कर्नवेशन में प्रावधान है कि यहां फैजादारी मुकदमें डालकर ज्ञात कर दें। अब व्यक्ति का धन वापस लाएंगे। राजनीतिक बहस से तो हम कर सकते हैं कि इन्हें दिनों में लाएंगे और इन्हां पैसा है, तेकिन इस व्यवस्था को हमारे लिए समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसमें एक कठिनाई और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2011 के फैसले में कहा है कि यह कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज जलत है। दुनिया कहती है कि बिना कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज के डम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्राप्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि यह विषय एसआईटी पर छोड़ दिया है और हम एसआईटी के सामने भी रख रहे हैं।

मैं इस सदन को विष्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार पूरा प्राप्त करेगी कि सौ दिन, पांच सौ दिन या हजार दिन, जितना भी समय लगे, जितने भी मठीने और वर्ष लगें, जब तक इनमें से आधिकारी खाते वाले को पकड़ कर नहीं लाया जाएगा, हम इस प्राप्त करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि एसआईटी भी इस विषय की खिंता कर रही है। इनकम टैक्स एवट में बाहर गाते का अधिकार नहीं है। गैंगे मनी टॉर्टिंग एवट का अद्यतन किया है, उसमें भी शायद कमज़ोरी है, तो भी बदलना पड़ेगा। अबर बाहर से नहीं लाए जाने के साक्षर हैं तो देश में उन्हें भी पैसे की उसकी जो सम्पत्ति है उसको कुछ करने का अधिकार होना चाहिए। इसे इनकम टैक्स में करें या मनी टॉर्टिंग में करें। यूनन कर्नवेशन में प्रावधान है कि यहां फैजादारी मुकदमें डालकर ज्ञात कर दें। अब व्यक्ति का धन वापस लाएंगे। राजनीतिक बहस से तो हम कर सकते हैं कि इन्हें दिनों में लाएंगे और इन्हां पैसा है, तेकिन इस व्यवस्था को हमारे लिए समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसमें एक कठिनाई और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2011 के फैसले में कहा है कि यह कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज जलत है। दुनिया कहती है कि बिना कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज के डम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्राप्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि यह विषय एसआईटी पर छोड़ दिया है और हम एसआईटी के सामने भी रख रहे हैं।

**श्री अर्जुन द्वारा (कटक) :** महोदय, वित्त मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी। I think, many of us have been convinced. One thing is relating to the issue that I have raised during my deliberations is that whether the names would be revealed or not.

One was the confidentiality clause. Yet, I would say that I beg to differ to what is being said because there are other provisions on which the Supreme Court has been insisting. I am not going into that issue now. But it is relating to the names that are to be revealed. पूरा देश जानना चाहता है कि फिन-विन के खाते वाले को पकड़ते हैं तो टैक्स किस माध्यम से करेंगे? मैं यह ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हमारे कानून में एक कमज़ोरी है और कमज़ोरी यह है कि जब पैसा पकड़ा जाएगा तो उसको वापस कैसे लाना है? उसको भी अब पूरा करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि एसआईटी भी इस विषय की खिंता कर रही है। इनकम टैक्स एवट में बाहर गाते का अधिकार नहीं है। गैंगे मनी टॉर्टिंग एवट का अद्यतन किया है, उसमें भी शायद कमज़ोरी है, तो भी बदलना पड़ेगा। अबर बाहर से नहीं लाए जाने के साक्षर हैं तो देश में उन्हें भी पैसे की उसकी जो सम्पत्ति है उसको कुछ करने का अधिकार होना चाहिए। इसे इनकम टैक्स में करें या मनी टॉर्टिंग में करें। यूनन कर्नवेशन में प्रावधान है कि यहां फैजादारी मुकदमें डालकर ज्ञात कर दें। अब व्यक्ति का धन वापस लाएंगे। राजनीतिक बहस से तो हम कर सकते हैं कि इन्हें दिनों में लाएंगे और इन्हां पैसा है, तेकिन इस व्यवस्था को हमारे लिए समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसमें एक कठिनाई और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2011 के फैसले में कहा है कि यह कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज जलत है। दुनिया कहती है कि बिना कॉनफिडेंशियलिटी वर्लॉज के डम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्राप्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि यह विषय एसआईटी पर छोड़ दिया है और हम एसआईटी के सामने भी रख रहे हैं।

**SHRI ARUN JAITLEY:** Madam Speaker, I will answer the second question first.

The DTC Bill is under our consideration. The earlier Government had drafted it. As far as the GST Bill is concerned, we have arrived at a broad consensus. There are some issues. The next meeting of the Empowered Committee has been called very shortly. I am confident that we will try and arrive at a consensus and possibly introduce the Bill in this Session itself. This is my endeavour and I hope that I will succeed in it.

As far as your first question is concerned about other clauses, please remember that there are well meaning people who made this suggestion. Our court has said this. Let us bring a legislation in India and that legislation will get us everything. I am not doubting it. They are very well meaning people but we are dealing with a case where the evidence is outside India. Whatever you do has to be consistent with international jurisprudence. The word in all these laws is that 'case is filed in a public court'. Now all commentaries, OECDs, interpretation of all other countries to this public court is whether charges are filed with evidence in a criminal court. Our Supreme Court said, "No, telling us is also a public court." We said, "We can tell you. We can tell the SIT. But through you, we cannot tell the world at large." Therefore, this inconsistency does exist and that is why, we went back to the court. On day one, the court reacted but on day two, they said to please go to the SIT as SIT is considering this issue. Unless our domestic procedures harmonise with international practices and interpretations, you may flex your muscles in your own country. As I said in the

other House yesterday, we can get a one day thrill of making the names public but if those countries do not accept our interpretation of international jurisprudence, then we will probably have 30 per cent withholding tax on us with the world not cooperating with us.

Therefore, what we have to look forward in this is not a bravado or adventurism but a thorough approach.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : But what about those who have settled the tax?

SHRI ARUN JAITLEY: Now as regards those who have settled the tax, if they are still guilty of a criminal offence, and with proof I move the court which is possible because the language is "in a public court", I can make it public when I go to a public court. I cannot make that phrase, "public court" disappear in the Tax Treaty. So, I am looking at not only criminal jurisprudence but also how the international jurisprudence has accepted that. Therefore, my own jurisprudence may take a particular interpretation, but it has to harmonise with the global standards.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): If I commit a murder and admit it, I will be excused!

SHRI ARUN JAITLEY: No, if you murder somebody, you will be arrested. But even there it is necessary that charges against you are filed in court. I will give you a simple example. The Reserve Bank permits you to repatriate 1.25 lakh dollars every year. Supposing you take the Reserve Bank's permission, take the money outside and open an account in Switzerland, your name will be given to us. But you say that it is an honest and legitimate account and I have transferred it by cheque from India with RBI's permission. Should I make you a subject of debate on the 9 o'clock television in the evening? Obviously, I cannot do that. Therefore, the international jurisprudence on the subject is, when I find that it is unlawful and I file charges against you in court, then you will be a subject matter of that debate and you will have your right of defence in the court.

Mahtab ji, if I falter in the procedure and make a hasty disclosure without evidence then I won't get the evidence and the account holders will have the last laugh. I am not willing for that.

HON. SPEAKER: Thank you very much.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Please permit me to seek a clarification.

HON. SPEAKER: This will go on like this. That is not the practice.

The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 28<sup>th</sup> November, 2014 at 11 a.m.

19.22 hrs

## **The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock**

on Friday, November 28, 2014/Agrahayana 7, 1936 (Saka).

\* गृहदय सुडग्हाद्युडक्कदक्क

\* गद्दय द्वड्दूहद्वड्दूक्कद्वड.

\* गृहदय खडकहृदखडकडकड.

\* गद्दय द्वडद्वहद्वडद्वडद्वड.

\* गृहदय खड़दहृदखड़कड़क

\* गद्दय द्वडद्वडद्वडद्वडद्वड.

\* गदय दददहदददददद.

\* गदय दददहदददददद.

\* गदय दददददददददद

## \* बहुत या द्वितीय द्वितीय द्वितीय द्वितीय